भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति-सिंहावलोकन

01
अध्याय

निराशा और अनिश्चितता, जिसकी चपेट में अनेक विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, के माहौल में वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न देशों के आर्थिक निष्पादन की तुलना करते समय एक आशाजनक लक्षण अनुकूल आर्थिक संभावनाओं वाली कुछ वृहत अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का उभरना रहा है। मुख्यत: इस तथ्य के कारण भारत की संभावनाएं उज्जवल हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी, निरंतर बनी मुद्रास्फीति, बढ़ते राजकोषीय घाटे, ढीली घरेलू मांग, विदेशी खाता असंतुलनों, और 2011-12 और 2012-13 में रुपये के बढ़ते-घटते मूल्य से जुड़ी असुरक्षाओं से काफी हद तक मुक्त हो गई है। बृहत आर्थिक दृष्टिकोण से कहें, तो हम संकट से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के हालिया संशोधित अनुमानों से आविर्भूत नवीनतम संकेतक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि विकास का समुत्थान 2013-14 में आरंभ हुआ था और 2014-15 में इसमें और भी तेजी आई। तेल की कीमतों में अत्यधिक गिरावट, विश्व के अन्य क्षेत्रों से निधियों की प्रचुर आवक और निर्दिष्ट आर्थिक प्रबंधन तथा समेकन के प्रति नई केन्द्रीय सरकार की प्रतिबद्धता के साथ इसकी सुधारात्मक पहलकदमियों के संभावित प्रभाव जैसे कारक उभरती वृद्धि के लक्षण और विकास संबंधी उभरती संभावनाओं और समग्र बृहत आर्थिक स्थिति के लिए हितकर हैं। बेहतर बृहत् आर्थिक स्थिरता और सरकार के सुधारवादी इरादे तथा कार्रवाइयों और देश में व्यवसाय के बेहतर माहौल से प्रोत्साहित होकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भारतीय विकास से संबंधित दृष्टिकोण का 2015 और इससे आगे के लिए स्तरोन्नयन कर दिया है। लेकिन ऐसे उज्जवल भविष्य के रास्ते में संभावित रुकावटों के मूल में, विशेषकर यूरोप और जापान में मांग की कमी रहने से ग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था से प्राप्त अपर्याप्त सहायता, चीन में हालिया मंदी तथा घरेलू मोर्चे पर, सामान्य से कम कृषि विकास के संभावित दुष्प्रभाव और कौशल-सृजन एवं अवसंरचनागत सुधार की बड़ी जरूरतों से संबंधित चुनौतियां हैं। 2014-15 के अग्रिम अनुमानों से प्राप्त उत्साहवर्धक नतीजों से यह पता चलता है कि वैश्विक विकास में व्याप्त शिथिलता ने विदेशी व्यापार में वृद्धि की चमक को अंशत: निगल लिया है; फिर भी विकास की चालू गति को चलायमान रखने वाली जबर्दस्त घरेलू मांग से इस गिरावट के दबाव की क्षतिपूर्ति हो गई।

विकास का हालिया वृत्तांत

1.2 वृहत हालिया आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करने से पूर्व, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2004-05 के पूर्ववर्ती आधार के स्थान पर 2011-12 के नए आधार को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रीय लेखाओं में सकल राशियों को हाल ही में संशोधित किया है (ब्यौरे के लिए

सारणी 0.1 : मुख्य संकेतक

आंकड़ों का वर्गीकरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. सघउ और संबंधित संकेतक					
सघउ (स्थिर बाजार कीमतें)	₹ करोड़	8832012[एनएस]	9280803[एनएस]	9921106[एनएस]	10656925[एई]
संवृद्धि दर	%	—	5.1	6.9	7.4
मूलय कीमतों पर जीवीए (2011-12 कीमतें)	₹ करोड़	8195546[एनएस]	8599224[एनएस]	9169787[एनएस]	9857672[एई]
वृद्धि दर	%	—	4.9	6.6	7.5
बचत दर	सघउ का प्रतिशत	33.9	31.8	30.6	उन
पूंजी निर्माण (दर)	सघउ का प्रतिशत	38.2	36.6	32.3	उन
प्रति पूंजी निवल राष्ट्रीय आय (वर्तमान बाजार कीमतों पर)	₹	64316[एनएस]	71593[एनएस]	80388[एनएस]	88533[एई]
2. उत्पादन					
खाद्यान्न	मिलियन टन	259.3	257.1	265.6	257.1[ए]
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक[बी] (वृद्धि)	%	2.9	1.1	-0.1	2.1[एफ]
विद्युत निर्माण (वृद्धि)	%	8.1	4.0	6.0	9.9 [एफ]
3. कीमतें					
मुद्रास्फीति (डब्ल्यू पी आई) (औसत)	%	8.9	7.4	6.0	3.4[एफ]
मुद्रास्फीति सीपीआई (आई डब्ल्यू)(औसत)	%	8.4	10.4	9.7	6.2[एफ]
4. विदेशी क्षेत्र					
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डॉलर)	%	21.8	-1.8	4.7	4.0[एफ]
आयात वृद्धि (अमरीकी डॉलर)	%	32.3	0.3	-8.3	3.6[एफ]
वर्तमान खाता शेष (सीएबी)/सघउ	%	-4.2	-4.7	-1.7	-1.9 (एच1)
विदेशी मुद्रा भंडार[जी]	अमरीकी डा. बिलियन	294.4	292.0	304.2	328.7
औसत मुद्रा दर[सी]	रु./अमरीकी डा. बिलियन	47.92	54.41	60.50	60.78[एफ]
5. मुद्रा और ऋण					
ब्राड मनी (एम3) (वार्षिक)	प्रतिशत परिवर्तन	13.5	13.6	13.2	11.5[एच]
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण	प्रतिशत परिवर्तन	17.0	14.1	13.9	10.7[एच]
6. राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	सघउ का प्रतिशत	5.7	4.8	4.5[डी]	4.1[ई]
राजस्व घाटा	सघउ का प्रतिशत	4.4	3.6	3.2[डी]	2.9[ई]
प्राथमिक घाटा	सघउ का प्रतिशत	2.7	1.8	1.2[डी]	0.8[ई]

टिप्पणी: एनए: अनुपलब्ध, एनएस: नई शृंखला अनुमान एई: अग्रिम अनुमान

एच1: अप्रैल-सितम्बर, 2014

[ए] दूसरा अग्रिम अनुमान

[बी] आधार (2004-05 = 100)

[सी] भारत के विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित और मई 2012 से आगे की संकेतात्मक दरें आरबीआई की संदर्भ दरें हैं

[डी] 2013-14 के राजकोषीय संकेतक अनंतिम वास्तविक पर आधारित हैं।

[ई] बजट अनुमान

[एफ] अप्रैल-दिसम्बर, 2014

[जी] 2011-12 से 2013-14 के आंकड़ों का संबंध वित्त वर्ष के अंत से है और 2014-15 के आंकड़े जनवरी, 2015 के अंत के हैं।

[एच] 09 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार

बॉक्स 1.1 : राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 करना

चालू आधार वर्ष का संशोधन जनवरी, 2010 में किए गए संशोधन के बाद का है। आधार वर्ष के अभी-अभी पूरे हुए संशोधन में शामिल किए गए प्रमुख फेरबदल निम्नलिखित हैं

(i) वर्तमान में विकास को स्थिर बाजार मूल्यों पर सघउ द्वारा मापा जाएगा, जिसे इसके बाद ''सघउ'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन है। इससे पूर्व, विकास को स्थिर मूल्यों पर कारक लागत पर सघउ में वृद्धि दर की दृष्टि से मापा जाता था।

(ii) जोड़े गए सकल मूल्य का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर किया जाएगा। कारक लागत पर जीवीए, मूल कीमतों पर जीवीए और सघउ (बाजार कीमतों पर) के बीच संबंध नीचे दिया गया है।

मूल कीमतों पर जीवीए = सीई + ओएस/एमआई + सीएफसी + उत्पादन कर रहित उत्पादन इमदाद

कारक लागत पर जीवीए = मूल कीमतों पर जीवीए - उत्पादन कर रहित उत्पादन इमदाद

सघउ = $\sum$ मूल कीमतों पर जीवीए + उत्पाद कर - उत्पाद इमदाद

(जहां सीई: कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति; ओएस: परिचालन अधिशेष; एमआई: मिश्रित आय; और सीएफसी: अचल पूंजी का उपभोग है। उत्पादन करों या उत्पादन इमदादों का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पादन से संबंधित होती है और ये वास्तविक उत्पादन के परिमाण पर आश्रित नहीं होते। उत्पादन करों के कुछ उदाहरण भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क तथा व्यावसायिक कर हैं। कुछ उत्पादन इमदादें रेलवे को इमदाद, किसानों को वस्तुगत इमदाद, गांवों और लघु उद्योगों को इमदाद, निगमों या सहकारी समितियों को प्रशासनिक इमदाद आदि हैं। उत्पादन करों या इमदादें का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पाद के प्रति यूनिट पर होती है। उत्पाद करों के कुछ उदाहरण उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर और आयात-निर्यात शुल्क है। उत्पाद इमदादों में खाद्यान्न, पेट्रोलियम और उर्वरक इमदाद, किसानों के परिवारों आदि को बैंकों के जरिए प्रदत्त ब्याज इमदाद, परिवारों का बीमा कराने के लिए कम दरों पर प्रदत्त इमदाद शामिल हैं।

(iii) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-अभिशासन पहल, एमसीए 21 के अंतर्गत उसमें यथा दर्ज कंपनियों के वार्षिक लेखाओं के समावेशन से विनिर्माण और सेवा दोनों ही कारपोरेट क्षेत्र की व्यापक कवरेज। विनिर्माण कंपनियों के एमसीए 21 डाटाबेस के उपभोग से इन कंपनियों द्वारा विनिर्माण से भिन्न किए गए कार्यों का हिसाब-किताब रखने में मदद मिली है।

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टाक ब्रोकर, स्टाक एक्सचेंजों, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, म्युचुअल फंडों और पेंशन फंडों, और पेंशन निधि एवं विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) सहित विनियामक निकायों के लेखाओं से सूचना के समावेशन से वित्तीय क्षेत्र को व्यापक सुरक्षा कवरेज।

(v) स्थानीय निकायों और स्वायत संस्थाओं के कार्यकलापों, जिनमें इन संस्थाओं को प्रदत्त लगभग 60 प्रतिशत अनुदान/अंतरण राशियां शामिल हैं, की संवर्धित कवरेज।

उपर्युक्त फेरबदलों के कारण, सकल और क्षेत्रवार दोनों स्तरों पर जीवीए के अनुमानों में परिवर्तन हुए हैं। सकल जीवीए में क्षेत्रवार शेयरों में खासकर विनिर्माण और सेवाओं के विशेष मामले में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है (चित्र 1)। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में अनुमान के लिए बिक्री कर और सेवा कर संबंधी आंकड़ों का उपयोग करने के कारण व्यष्टि क्षेत्रों में जीवीए की वृद्धि दरों और समग्र जीवीए में पण्य क्षेत्र के अंशदान में भी परिवर्तन देखे गए हैं। पूर्ववर्ती श्रृंखला से नयी श्रृंखला के अनुमानों और वृद्धि दरों की तुलना करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

चित्र 1: प्रचलित मूल्यों पर, उपादान लागत पर सकल मूल्य योजित (जीवीए) स्थिति में विभिन्न सेक्टरों की प्रतिशत हिस्सेदारी 2011-12 से 2013-14 का औसत

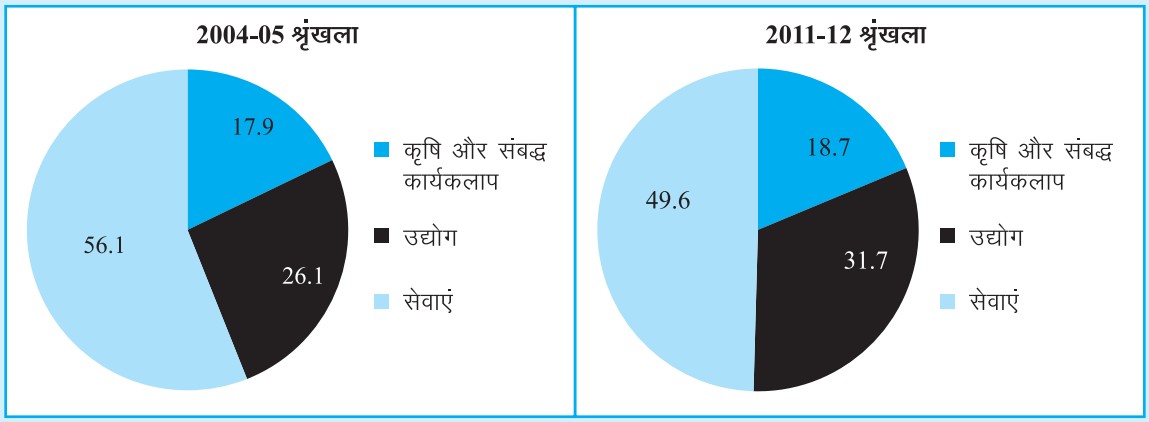

कृपया बॉक्स 1.1 देखें)। उपलब्ध सूचना के अनंतिम और आंशिक स्वरूप जिसे स्थिर होने में समय लग सकता है और इस तथ्य कि संशोधित आधार पर विकास संबंधी पैरामीटर तीन वर्षों के लिए ही उपलब्ध हैं, को देखते हुए व्यापक वृहत आर्थिक रुझानों को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में उद्देश्यपरक विश्लेषित करना कठिन हो सकता है। नयी सूचनावली की तुलना भी 2004-05 की श्रृंखला पर आधारित सूचना और विश्लेषण से नहीं की जा सकती।

1.3 नयी श्रृंखला (2011-12 को आधार वर्ष मानकर) द्वारा प्रस्तुत आर्थिक परिदृश्य से पता चलता है कि 2013-14 में अर्थव्यवस्था की कुछ वृहत् कुल राशियों में अवगम्य सुधार हुआ था, जिसमें 2014-15 में मजबूती आई। स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि से मापा गया आर्थिक विकास, जो 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत आंका गया था, वह मई 2014 में 2004-05 श्रृंखला के अंतर्गत जारी 4.7 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत के तदनुरूप आंकड़ों से उच्च था। यह तथ्य थोड़ा उलझन में डालने वाला है कि यह उच्च वृद्धि उस वर्ष में हुई जब सघउ अनुपातों में बचत और निवेश दोनों अनेक वर्षों के औसत से अल्प थे और जब आयातों (जो सामान्यतया सघउ से सकारात्मक रूप में जुड़े होते हैं) का स्तर दरअसल 10 प्रतिशत के करीब वास्तविक रूप से घट गया था। 2013-14 के लिए सघउ की वास्तविक वृद्धि दर के मजबूत प्रतीत होने के अनेक कारणों में से एक कारण 2011-12 और 2012-13 में सघउ का स्तर अल्प होने के साथ-साथ सघउ के अपस्फीति कारकों का स्तर समझे गए स्तर से निम्न होना है।

सारणी 1.1 : पुरानी और नई श्रृंखला की तुलना

मद	वर्ष	नई श्रृंखला और पुरानी श्रृंखला के बीच प्रतिशतांक में अंतर
कारक लागत पर जीवीए में वृद्धि	2012-13	0.4
	2013-14	1.9
अपस्फीतिकारक में वृद्धि	2012-13	0.5
	2013-14	-0.3
वर्तमान कीमतों पर कारक लागत पर जीवीए का स्तर	2011-12	-2.2
	2012-13	-1.3
	2013-14	0.2

स्रोत : सीएसओ।

1.4 सारणी 1.1 में ये प्रभाव कारक लागत पर जीवीए की नयी एवं पुरानी श्रृंखला के आधार पर पृथकतः प्रदर्शित किए गए हैं। जीवीए का स्तर इन सभी तीन वर्षों में घटा और इसके साथ ही उत्तरवर्ती वर्षों में ह्रासमान गिरावट का स्तर भी देखा गया। (इसका सत्यापन 2014-15 के लिए अनुमानों के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके लिए नई श्रृंखला से ही आंकड़े उपलब्ध हैं। 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की तुलना में 2011-12 में सघउ के स्तर में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट से उत्तरवर्ती वर्षों में विकास दर में सुधार हुआ है। दूसरी ओर सघउ के अस्फीति कारक द्वारा मापे गए, 2012-13 में मुद्रास्फीति के अर्ध्वमुखी संशोधन से विकास की स्थिति बदतर हुई, परंतु यह इतनी भी बदतर नहीं हुई कि संपूर्ण स्तरों में सापेक्ष संशोधनों के सकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय कर सके। 2013-14 में, अपस्फीतिकारक में अधोमुखी संशोधन से नई श्रृंखला में विकास में सुधार हुआ।

सारणी 1.2 : स्थिर (2011-12) मूल कीमतों पर जीवीए में वृद्धि (प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	**1.2**	**3.7**	**1.1**
उद्योग	**2.3**	**4.5**	**5.9**
खनन और उत्खनन	-0.2	5.4	2.3
विनिर्माण	6.2	5.3	6.8
विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	4.0	4.8	9.6
निर्माण	-4.3	2.5	4.5
सेवाएं	**8.0**	**9.1**	**10.6**
व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन और संचार	9.6	11.1	8.4
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यवसाय सेवाएं	8.8	7.9	13.7
समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	4.7	7.9	9.0
मूल कीमतों पर जीवीए	**4.9**	**6.6**	**7.5**
सघउ (बाजार कीमतों पर)	**5.1**	**6.9**	**7.4**

स्रोत : दिनांक 30 जनवरी, 2015 और 9 फरवरी, 2015 के सीएसओ प्रेस नोट पर आधारित।

1.5 भिन्न-भिन्न पृथक किस्म के स्तर (सारणी 1.2) के अनुमानों से जाहिर होता है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की फसलों, पशुधन, वानिकी और वृक्षकर्तन (लागिंग) तथा मत्स्य पालन सहित 2013-14 में वृद्धि में सुधार हुआ। यह अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि वर्ष 2013-14 वर्षा होने की दृष्टि से असाधारणतया अच्छा वर्ष साबित हुआ।

1.6 विनिर्माण क्षेत्र में 2012-13 और 2013-14 में क्रमश: 6.2 प्रतिशत और 5.3 की वृद्धि (कारक लागत पर जीवीए की दृष्टि से 6.1 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत) दर्ज हुई। पूर्व संशोधितशृंखला के अनुसार, यह वृद्धि 1.1 प्रतिशत और (-) 0.7 प्रतिशत रही। वृद्धि दर में इस आश्चर्यजनक फेरबदल का श्रेय आंकड़ों के सामान्य संशोधनों को दिया जा सकता है, जो आधार परिवर्तन और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के एमसीए 21 डाटाबेस के समावेशन और कारपोरेट क्षेत्र की अधिक व्यापक कवरेज के प्रभाव से संशोधन अनुसूचियों के अनुसार घटित होते हैं। उदाहरणार्थ पूर्ववर्ती प्रणाली और 2004-05 की शृंखला के आधार पर भी, फरवरी 2012 में जारी अनुमानों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर में जारी अनुमानों के अनुसार 3.9 प्रतिशत थी, जो जनवरी 2013 में संशोधित होकर 2.7 प्रतिशत और जनवरी 2014 में 7.4 प्रतिशत रही। इसका आशय यह है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास में 2012-13 और 2013-14 में आधार वर्ष में संशोधन के बिना भी कुछ और हो सकता था। नई शृंखला में विनिर्माण वृद्धि में ऊर्ध्ववर्ती संशोधन का कारण भी विनिर्माण कंपनियों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में ही किए गए व्यापार, जो पहले व्यापार सेवाओं का भाग था, का समावेशन रहा।

1.7 नई शृंखला के पृथक स्तर पर, विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि को मुख्यत: कपड़ा परिधानों और चर्म उत्पादों में मजबूत वृद्धि से बल मिला, जिसकी औसत वृद्धि 2012-13 और 2013-14 में 17.7 प्रतिशत रही थी, और इसी अवधि में मशीनरी तथा उपस्कर क्षेत्र की औसत वृद्धि 9.3 प्रतिशत रही। खाद्य उत्पादों की गति में अभी वृद्धि होना शेष है।

1.8 सेवा क्षेत्र में विकास की गति में 2013-14 में तेजी आई। व्यापार और मरम्मत सेवाओं, रेल परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं तथा विविध सेवाओं जैसी सेवाओं में इस वर्ष के दौरान दोहरे अंकों/दोहरे अंकों के करीब की विकास दर प्राप्त हुई। किन्तु, जल परिवहन और भंडारण सेवाओं जैसे क्षेत्र पिछड़ गए।

1.9 वर्तमान वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि 2013-14 में प्रकट हुए सकारात्मक वृद्धि के रुझान औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में 2014-15 में सुदृढ हुए है, जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 में मूल कीमतों पर जीवीए में 0.9 प्रतिशतांक की वृद्धि और सघउ में 0.5 प्रतिशतांक तक सुधार हुआ। जबकि विद्युत, गैस और जलापूर्ति तथा उपयोगिता संबंधी अन्य सेवाओं में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है, तथापि विनिर्माण क्षेत्र ने अपना संवेग सुदृढ़ कर लिया है। निर्माण क्षेत्र का निष्पादन बेहतर हुआ है जबकि खनन और उत्खनन कार्यकलापों में अभी अस्थायी पैटर्न दिखता है। समुचित नीतिगत परिवर्तनों के साथ, कोयला क्षेत्र ने इस बंधन को तोड़ दिया है और अप्रैल-दिसम्बर, 2013-14 के दौरान इसमें 9.1 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। तथापि, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों की स्थिति में गिरावट बनी रही, जिससे खनन के समग्र परिदृश्य को क्षति पहुंची। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से प्राप्त संकेतों के साथ राष्ट्रीय लेखाओं की नई शृंखला से औद्योगिक क्षेत्र, खासकर विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित परिणामों का समाधान करना कठिन है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उत्पादक इकाइयों के सीमित नमूने पर आधारित होता है, जबकि राष्ट्रीय लेखाओं की नई शृंखला, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, एमसीए 21 और आईआईपी सहित विविध आंकड़ों का उपयोग करती है।

1.10 चालू वर्ष द्वारा सभी प्रधान सेवा क्षेत्रक कार्यकलापों में बेहतर निष्पादन कर चुकने का अनुमान किया गया है। वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा, और व्यवसाय सेवाएं, जो हालिया वर्षों में अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक गतिशील क्षेत्रों में से एक क्षेत्र रहा है (संशोधन पूर्व आंकड़ों के अनुसार), की वर्तमान वर्ष में वृद्धि के अग्रसर होने की संभावना है।

1.11 आधारिक संशोधन से यह भी पता चलता है कि कारक लागत पर समग्र जीवीए में कृषि क्षेत्रक अंशदान पूर्ववर्ती शृंखला (2004-05) के आधार पर अब दिखाए जा रहे अंशदान से थोड़ा-सा उच्च है। वर्तमान मूल कीमतों पर जीवीए में 18.1 प्रतिशत के कुल हिस्से में फसल-अर्थव्यवस्था का अंशदान 11.8 प्रतिशत था जबकि संबद्ध क्षेत्रों का अंशदान में हिसाब 6.3 प्रतिशत बैठता था। इसके अलावा, सेवागत उच्च वृद्धि के बावजूद, पुरानी शृंखला में विनिर्माण जीवीए के न्यूनानुमान और सेवा में 'व्यापार' क्षेत्रक सघउ के अति-अनुमान में संशोधन के मुख्य कारण से औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में क्षेत्रक अंशदान का पुनर्निर्धारण हुआ है। (सारणी 1.3)।

सारणी 1.3 : वर्तमान कीमतों पर जीवीए में हिस्सा

क्षेत्र	2004-05 शृंखला			2011-12 शृंखला			
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	17.9	17.5	18.2	18.9	18.7	18.6	17.6
उद्योग	27.2	26.2	24.8	32.9	31.7	30.5	29.7
सेवाएं	54.9	56.3	57.0	48.2	49.6	50.9	52.7

स्रोत : राष्ट्रीय आय की नयी शृंखला के अनुमानों पर 30 जनवरी, 2015 और 9 फरवरी, 2015 की सीएसओ की प्रेस विज्ञप्तियां।

1.12 कुल मिलाकर, तीन वर्ष खंड 2011-12 से 2013-14 तक के लिए पुरानी शृंखला 26.1 प्रतिशत से नई शृंखला के तहत 31.7 प्रतिशत होने से औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में 5.6 प्रतिशतांक का ऊधर्ववर्ती संशोधन हुआ। इसके तदनुरूप, 6.5 प्रतिशतांक के अधोमुखी संशोधन से सेवा क्षेत्र का औसत अंशदान 56.1 प्रतिशत से 49.6 प्रतिशत पर रह गया। इस अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हिस्से में भी 0.9 प्रतिशतांक वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में उचित वृद्धि के बावजूद, सेवा क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि होने के कारण इसके जीवीए का हिस्सा 2014-15 में घट गया। यह देखा गया है कि कुल जीवीए वृद्धि में सेवा क्षेत्र का अंशदान 2013-14 में 68.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 72.4 प्रतिशत हो गया, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों के तदनुरूप आंकड़े परिवर्तित होकर क्रमश: 9.8 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत और 22.1 प्रतिशत से 25.1 प्रतिशत तक रह गए।

तिमाही वार रुझान

1.13 विकास के तिमाही वार अंक वृद्धिगत संवेग के निधारण में उपयोगी होते हैं 2014-15 के पूर्ण वर्ष के लिए विकास के अग्रिम अनुमानों और प्रथम तीन तिमाहियों के अनुमानों की तुलना करने पर यह पाया जाता है कि 2014-15 की चौथी तिमाही के लिए 7.8 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित है (सारणी 1.4)।

1.14 विकास के त्रैमासिक आंकड़ों से पता चलता है कि विकास संबंधी गति 2014-15 की सभी तिमाहियों में बनी रही है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मंदी का प्रभाव और अद्यौगिक क्षेत्र में सामान्य वृद्धि तीसरी तिमाही में वृद्धि में हल्की गिरावट का कारण हो सकती है।

1.15 राष्ट्रीय लेखाओं की 2004-05 शृंखला तथा संशोधन (2011-12) शृंखला में देश के सघउ में त्रैमासिक अंशदान में किंचित अंतर देखे गये हैं। संशोधित शृंखला में यह दृश्यमान है कि वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में वर्तमान कीमतों पर कुल सघउ लगभग 47 प्रतिशत के हिसाब बैठता है, जबकि इसके उत्तरार्ध में यह 53 प्रतिशत बैठता है। 2004-05 शृंखला के लिए वर्तमान बाजार मूल्यों पर सघउ में यही पैटर्न देखा गया है, जिसमें पूर्वार्ध के लिए कुल सघउ 46 प्रतिशत बैठता था जबकि उत्तरार्ध के लिए यह 54 प्रतिशत बैठता था।

उत्पादन मूल्य और योजित मूल्य

1.16 सकल उत्पाद मूल्य (जीवीओ) और योजित सकल मूल्य (जीवीए) के बीच अंतर मध्यवर्ती उपभोग के रूप में है। सारणी 1.5 (स्तम्भ 5 और 6) में प्रस्तुत जीवीए और जीवीओ में क्षेत्रक हिस्सों में विरोधाभास सारणी के स्तंभ 2 से 4 में प्रस्तुत मूल्य योजन के अनुपातों में अंतरों को प्रतिबिंबित करता है।

सारणी 1.4 : मूल कीमतों पर जीवीए में तिमाही-वार वृद्धि (वर्षानुवर्ष) (2011-12)

क्षेत्र	2013-14				2014-15		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
कृषि: वानिकी और मत्स्य पालन	2.7	3.6	3.8	4.4	3.5	2.0	-0.4
उद्योग	4.8	4.0	5.0	4.3	6.1	6.0	3.9
सेवाएं	10.2	10.6	9.1	6.4	8.6	10.1	13.5
कुल जीवीए मूल कीमतों पर	7.2	7.5	6.6	5.3	7.0	7.8	7.5

स्रोत : सीएसओ की 9 फरवरी, 2015 की प्रेस विज्ञप्ति।

सारणी 1.5 : जीवीए और जीवीओ (स्थिर मूल्यों पर) के बीच संबध

मद	क्षेत्रीय जीवीए का क्षेत्रीय जीवीओ के प्रति अनुपात			कुल जीवीओ* में क्षेत्रवार जीवीओ का अनुपात	कुल जीवीए* में क्षेत्रवार जीवीए का अनुपात	जीवीओ में वृद्धि (प्रतिशत में)	
	2011-12	2012-13	2013-14			2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	77.1	77.2	77.3	10.4	17.8	1.0	3.6
उद्योग	25.4	26.4	26.5	55.9	32.4	-1.6	3.9
विनिर्माण	20.5	22.2	22.4	37.7	18.2	-1.8	4.3
सेवाएं	65.7	66.6	67.6	33.7	49.9	6.5	7.4
कुल	43.8	45.4	46.0	100.0	100.0	1.3	5.1

टिप्पणी : गणनाएं 2011-12 से 2013-14 तक के के.सां.का. आंकड़े; *औसत पर आधारित हैं।

1.17 जीवीओ में योजित सकल मूल्य के अनुपात से यह दिखता है कि कृषि में मूल्य योजन उच्चतम और विनिर्माण में न्यूनतम है। जीवीओ के हिस्सों और जीवीए के अंशों के बीच का अंतर सभी क्षेत्रों खासकर विनिर्माण क्षेत्र में अत्यधिक है। एक ओर, विनिर्माण में जीवीओ में जीवीए का अल्प अनुपात यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग का सृजन करता है और दूसरी ओर, यह कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को समग्र जीवीए में अपने योगदान को सुधारने हेतु मूल्य शृंखला को अर्ध्वमुखी करने की जरूरत है।

1.18 सारणी 1.2 और 1.5 में प्रस्तुत आंकड़ों से, यह पता चलता है कि विनिर्माण के मामले में, 2012-13 में जीवीओ (स्थिर मूल्यों पर) में 1.8 प्रतिशत की कमी आई, जबकि वास्तविक जीवीए में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके साथ ही, जीवीओ के मुकाबले जीवीए का अनुपात महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा (सारणी 1.5)। इसके अलावा, विनिर्माण में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्थिर मूल्यों पर जीवीए में नियत पूंजी के उपभोग का अनुपात 2011-12 में 17.5 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 17.1 प्रतिशत रह गया। इसलिए, संकुचन के परिणाम के बावजूद, क्षेत्र के विनिर्माण में कारक आयों में जीवीए में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। इसी तरह, सेवाएं क्षेत्र में, 2012-13 में जीवीए में वृद्धि इसी वर्ष में जीवीओ में हुई वृद्धि के मुकाबले में 1.5 प्रतिशतांक उच्च रही।

1.19 सारणी 1.1 और 1.4 से, यह भी देखा जा सकता है कि 2013-14 में भी विनिर्माण और सेवाओं में जीवीए में हुई वृद्धि के परिणाम जीवीओ में हुई वृद्धि के परिणाम से उच्च बने रहे। विनिर्माण में, 2013-14 में जीवीओ वृद्धि सकारात्मक (4.3 प्रतिशत) रही, परन्तु यह जीवीए में हुई वृद्धि से काफी कम रही। विनिर्माण और सेवाओं में इन उभरते रुझानों से मूल्य योजन में सुधार का संकेत मिलता है। अत: एक तरह से उत्पादन में वृहत्तर सक्षमता को प्रोत्साहन मिल रहा है।

सकल मांग

1.20 हालिया वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति की गंभीर कमियों से गुजरी है। 2013-14 में मजबूती से विकास के साथ, अर्थव्यवस्था में अंतिम उपभोग व्यय (स्थिर मूल्यों पर वर्णित) भी सुदृढ़ हुआ (सारणी 1.6)।

1.21 पूंजी निर्माण दर में अत्यधिक गिरावट के कारण सकल मांग पर प्रतिकूल प्रभाव रहा (सारणी 1.6), जिससे घरेलू समामेलन (उपभोग और निवेश मिलाकर) संकुचन से इसमें 2013-14 में केवल 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बावजूद, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में 7.4 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के आधार पर 7 प्रतिशत के समीप वृद्धि हासिल की गई और आयातों में 8.4 प्रतिशत तक की कमी आयी।

1.22 2013-14 के दौरान सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की दर में कमी समग्र निवेश दर (सकल पूंजी निर्माण-जीसीएफ) में उद्घोषित दर की तुलना में काफी कम थी, क्योंकि जीसीएफ के अन्य दो संघटकों, अर्थात स्टाक और मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन, में महत्वपूर्ण

सारणी 1.6 : स्थिर (2011-12) बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15(A)
कुल अंतिम उपभोग व्यय	4.9	6.5	7.6
निजी अंतिम उपभोग व्यय	5.5	6.2	7.1
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	1.7	8.2	10.0
सकल पूंजी निर्माण*	2.6	-4.0	उन
सकल नियत पूंजी निर्माण	-0.3	3.0	4.1
स्टाक में परिवर्तन	-6.2	-21.4	3.9
कीमती वस्तुएं	3.3	-48.7	28.2
निर्यात	6.7	7.3	0.9
आयात	6.0	-8.4	-0.5
स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि	5.1	6.9	7.4

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : क: अग्रिम अनुमान; *भूल-चूक के लिए समायोजित सकल पूंजी विनिर्माण।

उन : उपलब्ध नहीं।

रूप से कमी आई (सारणियां 1.5 और 1.6)। वस्तु-सूचियों के स्टाक में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जो मांग और आपूर्ति शर्तों द्वारा निर्धारित की जाती है और अर्थव्यवस्था के पूंजी आधार से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित नहीं है। इसी तरह, 'मूल्यवान वस्तुएं', जो स्वर्ण, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के संचयन से संबंधित हैं, उत्पादक आधार में समायोजित नहीं की जाती हैं। इसलिए, इन वस्तुओं में गिरावट, यद्यपि लेखांकन की दृष्टि से इससे निवेश में सीमित सुधार होता है, पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निरंतर और संवर्धित विकास के लिए 2011-12 से 2013-14 तक नियत निवेश दर (सारणी 1.7) में लगभग चार प्रतिशतांक की कमी पूरा करने की आवश्यकता होगी। उपभोग के दीर्घावधि रुझानों के विपरीत, मुख्यरूप से सरकारी उपभोग व्यय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के कारण, गत तीन वर्ष के दौरान उपभोग के औसत रुझान में वृद्धि देखी गई (सारणी 1.7)। इससे विकास को आंशिक रूप से अपेक्षित मांग संवेग उपलब्ध होने की संभावना है।

1.23 2014-15 में स.घ.उ. के मांग पक्ष ने मिश्रित रुझान प्रस्तुत किए। पहला, निजी और सरकारी उपभोग दोनों में सुदृढ़ वृद्धि दर्शाते हुए उपभोग में बढ़ती प्रवृत्तियां क्रमिक रूप से मजबूत हुई हैं (सारणियां 1.6 और 1.7)। दूसरा, अर्थव्यवस्था में नियत पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है, परन्तु सकल मांग में हिस्सा नहीं रहा। तीसरा, निर्यातों से विकास को शायद ही कोई सहायता मिली है। आयातों में गिरावट मूलत: चालू वर्ष में अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में जबरदस्त कमी के कारण रही है जिससे तेल आयात हुंडी में कमी आई है। इसलिए, एक एहतियाती निष्कर्ष यह हो सकता है कि सतत् विकास पुनरुद्धार मुख्य रूप से घरेलू उपभोग से अभिप्रेरित है।

1.24 चित्र 1.1 से देशों के बीच स.घ.उ. के अनुपात में सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) और विकास दरों की तुलना सूचित करती है कि ब्रिक्स देशों (और इंडोनेशिया) के बीच भारत निम्नतम वृद्धिशील पूंजी परिणाम अनुपातों (जीएफसीएफ आधारित-आईसीओआर) को प्रचालित करता है। 2012-13 और 2013-14 के लिए 29 प्रतिशत की

सारणी 1.7 : स.घ.उ. में व्यय संघटकों की दरें

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. अंतिम उपभोग व्यय	68.8	69.7	71.0	72.1
2. सकल पूंजी निर्माण	38.2	36.6	32.3	उन
सकल नियत पूंजी निर्माण	33.6	31.4	29.7	28.6
स्टॉक में परिवर्तन	2.4	2.1	1.6	1.5
मूल्यवान वस्तुएं	2.9	2.8	1.3	1.3
3. वस्तुओं और सेवाओं का निवल निर्यात	-6.4	-6.7	-2.9	-2.4

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : सांख्यिकी विसंगतियों के कारण हिस्से नहीं जुडेंगे; उन : उपलब्ध नहीं।

चित्र 1.1: 2013, में ब्रिक्स देशों और इंडोनेशिया में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में मांग पक्ष के घटक

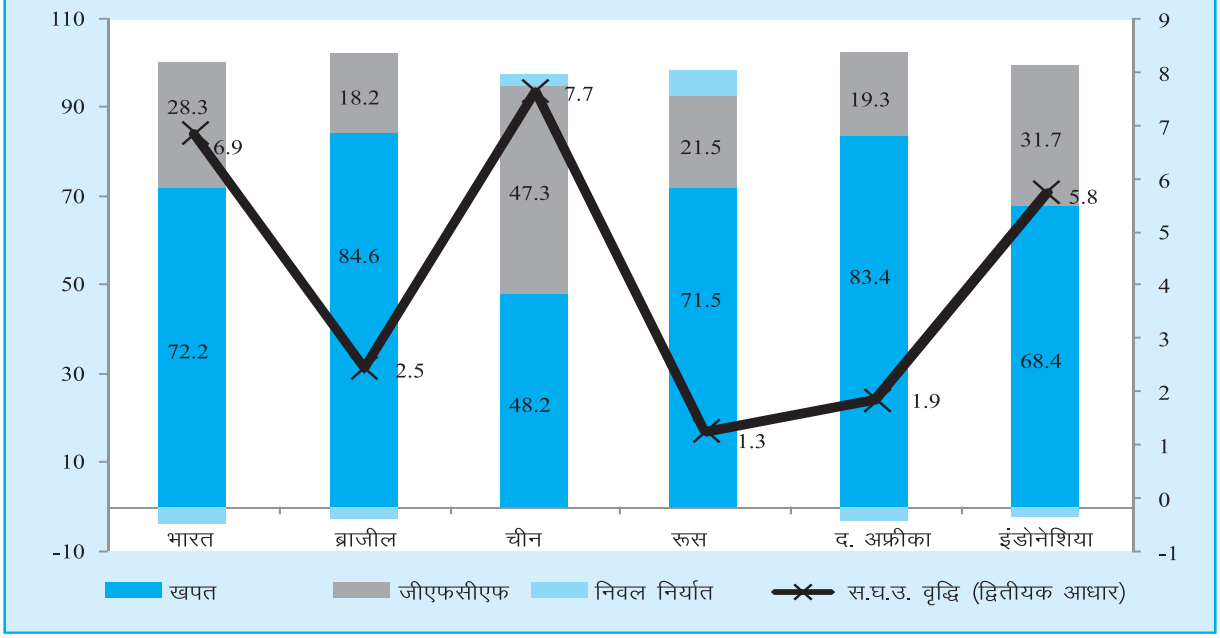

स्रोत : विश्व बैंक आंकड़ा आधार, भारत की विकास दर को छोड़कर जो सीएसओ से है।

***टिप्पणी* : भारत के लिए, आंकड़े वित्त वर्ष 2013-14 के लिए हैं।**

औसत नियत निवेश दर देकर, और इन वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की औसत स.घ.उ. विकास दर देकर, आईसीओआर 4.8 बैठती है। 2014-15 में विकास दर 7.4 प्रतिशत तक सुधरने और जीएफसीएफ के अनुपात में मामूली गिरावट के साथ (जीएफसीएफ की विकास दर में वृद्धि के बावजूद), भारत के लिए आईसीओआर और भी गिर गया।

1.25 पूर्व-संशोधित श्रंखला से उपलब्ध बचत दर (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचतें) में पूर्व प्रवृत्तियों से, यह देखा गया है कि यह 2007-08 में इसके ऐतिहासिक स्तर (36.8 प्रतिशत) पर पहुंच गई और तत्पश्चात् सामान्य अधोगामी संवेग के साथ, यह अस्थिर बनी रही। जहां निजी कारपोरेट बचतों में तेजी से गिरावट आई, वहीं वित्तीय बचत लागत पर घरेलू बचतें भौतिक आस्तियों के संचयन के पक्ष में पुनर्निर्धारण की साक्षी रहीं। बचतों में संयोजकपरक परिवर्तनों के संकेतों को नई श्रंखला के तीन वर्षों पर आधारित आंकड़ों से देखा जा सकता है।

1.26 जबकि बचत की पुरानी श्रृंखला कई कारणों से नई श्रृंखला (2011-12 आधार) के साथ सटीक रूप से तुलनीय नहीं है। इन कारणों में बचत के भाग के रूप में 'मूल्यवान वस्तुओं' का नया समावेशन शामिल है। नई श्रृंखला से तीन वर्षों के आंकड़े सुझाते हैं कि भौतिक आस्तियों के लिए घरेलू अधिग्रहण में गिरावट आ रही (सारणी 1.8)। पृथक आंकड़ों ने यह भी दर्शाया कि 2011-12 में घरेलू मदों

सारणी 1.8 : बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल बचत

	2011-12	2012-13	2013-14
सकल बचत	33.9	31.8	30.6
सरकारी	1.4	1.7	1.6
निजी कारपोरेट	9.7	10.0	10.9
घरेलू	22.8	20.2	18.2
भौतिक*	15.5	13.2	11.0
वित्तीय	7.3	7.0	7.2

***स्रोत* : सीएसओ।**

***टिप्पणी* : *घरेलू भौतिक बचतों में मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल हैं।**

की वित्तीय आस्तियों में वार्षिक संवर्धन सकल बचतों के 31.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 36.8 प्रतिशत होने के बावजूद, घरेलू मदों की वित्तीय बचतों की दर में अपवृद्धि नहीं हुई (सारणी 1.8) क्योंकि इनकी वित्तीय देयताएं भी साथ-ही सकल बचतों के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गईं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान आस्ति पक्ष पर, घरेलू मदों की अतिरिक्त बैंक जमाओं में 27.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि देयता पक्ष पर, बैंक अग्रिमों में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.27 गैर-प्रचालित अधिशेष/घाटा के लिए समायोजित निजी कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिधारित लाभों, जो राष्ट्रीय लेखाओं के अंतर्गत उनकी बचत के रूप में परिभाषित किए गए हैं, में पुरानी श्रृंखला द्वारा प्रकटित प्रवृत्तियों के विपरीत 2011-12 से 2013-14 के दौरान वृद्धि हुई (सारणी 1.8)। यह पुरानी श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित उन रुझानों के विपरीत है, जिनमें यह दर्शाया गया था कि निजी कारपोरेट बचतें 2011-12 में स.घ.उ. का केवल 7.3 प्रतिशत थीं और ये 2012-13 में 7.1 प्रतिशत तक गिर गयी। गैर-वित्तीय निगमों के कंपनी वित्तपोषण पर भारतीय रिजर्व बैंक के नमूना अध्ययनों की तुलना में कंपनियों के काफी अधिक विस्तृत कवरेज के एमसीए 21 आंकड़ा-आधार के भरोसे (जो पुरानी श्रृंखला के लिए आंकड़ों का स्रोत था) ने अनुपातों और उनकी प्रवृत्तियों में पूर्व-प्रदर्शित संशोधन को प्रकट किया है। नई श्रृंखला के अनुसार, स.घ.उ. के अनुपात में निजी गैर-वित्तीय निगमों की बचतें 2011-12 में 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 9.5 प्रतिशत हो गईं जबकि निजी वित्तीय निगमों की बचत दर में केवल मामूली परिवर्तन हुआ।

1.28 2011-12 से 2013-14 तक सरकारी क्षेत्र बचत के संयोजन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि सामान्य सरकार की निर्बचत कम हो गई जो इस अवधि के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त राजस्व घाटे में कमी के अनुरूप है। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा 2011-12 के 4.1 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 3.7 प्रतिशत और 2013-14 में और भी घटकर 2.9 प्रतिशत रह गया।

1.29 निवेश से बचत की तुलना करने पर (सारणियां 1.8 और 1.9), यह स्पष्ट है कि निजी कारपोरेट क्षेत्र में न्यून उद्घोषित अंतराल से अनुपूरित समेकित सरकारी क्षेत्र का बचत-निवेश अंतरल बड़ा था जिसका घरेलू मदों की बचतों, जिन्होंने सकल बचत-निवेश अंतराल का सृजन किया, द्वारा पूर्णतया भुगतान नहीं किया जा सकता था। घरेलू बचतों और घरेलू निवेश के बीच अंतर पारिभाषिक रूप से चालू खाता शेष (सारणी 1.9 में निवल पूंजी अंतर्वाह) के समकक्ष है। उपर्युक्त के मद्देनज़र, यह स्पष्ट है कि बचत-निवेश अंतराल को स्वीकार्य स्तरों पर रखने के लिए घरेलू वित्तीय बचत को ऊपर रखने की आवश्यकता है।

सारणी 1.9 : स.घ.उ. के अनुपात में निवेश (वर्तमान बाजार मूल्य प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14
सकल पूंजी निर्माण	38.2	36.6	32.3
सरकारी क्षेत्र	7.6	7.2	8.0
निजी क्षेत्र	28.4	26.3	23.3
कारपोरेट क्षेत्र	13.3	13.5	12.6
घरेलू क्षेत्र	15.1	12.9	10.7
सकल बचतें	33.9	31.8	30.6
बचत निवेश अंतराल	-4.3	-4.8	-1.6
निवल पूंजी अंतर्वाह	4.3	4.8	1.6

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : भूल-चूक के लिए समायोजन के कारण आंकड़े मेल नहीं खा सकते हैं।

1.30 पूंजी निर्माण का संयोजन इसकी उत्पादकता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। इसका निर्धारण मोटे तौर पर मशीनरी और निर्मित संरचनाओं के बीच अपेक्षित संपूरकताओं द्वारा किया जाएगा। सारणी 9 सूचित करती है कि बौद्धिक संपदा उत्पादों का समायोजन, जो क्रमिक रूप से अपवर्धित हो रहा है, नई श्रृंखला में पूंजी निर्माण के भाग के रूप में पृथक् रूप से दर्शाया जाता है। सारणी 1.10 दर्शाती है कि बौद्धिक संपदा उत्पादों जो नई श्रृंखला में पूंजी निर्माण के अंतर्गत अलग से दिखाया गया है, में वृद्धि शनैः शनैः तेज हो रही है। इससे यह भी पता चलता है कि निर्माण नियत पूंजी में वृद्धि का मुख्य भाग है। आवासीय इकाइयों का निर्माण, निर्माण की अवधि के दौरान आय और रोजगार में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है और निवेश क्षेत्रों और स्थावर भू-संपदा सेवाओं में मांग के सृजन के जरिए बड़ी उत्पादनोत्तर और उत्पादन-पूर्व सहबद्धताओं का सृजन करता है। (निवेश विनिवेश सारणियां 2007-नवीनतम उपलब्ध-विभिन्न क्षेत्रों के बीच इंगित करती है कि अर्थव्यवस्था में निर्माण की उच्चतम सहबद्धताएं हैं)।

1.31 तथापि, निर्माण संबंधी आवासीय यूनिटें अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में कोई स्थायी योगदान करने वाली नहीं समझी जा सकती हैं। आंकड़े अन्य निर्माण जैसे सड़क, रेल नेटवर्क सिंचाई संबंधी निर्माण, आदि से पृथक् रूप में

सारणी 1.10 : कुल जीएफसीएफ की प्रतिशत के रूप में संघटक

	2011-12	2012-13	2013-14
आवासीय, अन्य भवन तथा संरचनाएं	59.3	58.2	58.6
मशीनरी और उपकरण	35.6	36.7	35.6
कृष्ट जैविक संसाधन	0.2	0.2	0.2
बौद्धिक संपदा उत्पाद	4.8	4.9	5.6

स्रोत : सीएसओ।

सारणी 1.11 : स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में घरेलू जीएफसीएफ

	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू जीएफसीएफ	15.0	12.6	10.6
जिनमें मकान, इमारतें और भवन शामिल हैं	12.7	10.6	8.9

स्रोत : सीएसओ।

आवासीय इकाइयों के निर्माण की जांच करने को अनुमत नहीं करते हैं।

1.32 परिवारों द्वारा आवासीय इकाइयों, अन्य भवनों और संरचनाओं का निर्माण अर्थव्यवस्था में कुल जीएफसीएफ का लगभग 34 प्रतिशत और 2011-12 से 2013-14 के दौरान घरेलू मदों की अपनी जीएफसीएफ का 84 प्रतिशत बैठता है। सारणी 10 दर्शाती है कि स.घ.उ. के अनुपात के रूप में घरेलू निर्माण का हिस्सा 2011-12 और 2013-14 के बीच 3.8 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिर गया। इसके साथ ही, यह सूचित करते हुए कि इस अवधि के दौरान नियत पूंजी निर्माण की दर में कमी घरेलू निर्माण में लगभग पूर्णतया गिरावट के कारण थी जिससे स.घ.उ. के अनुपात में कुल जीएफसीएफ 3.9 प्रतिशत बिन्दुओं तक नीचे आ गई (सारणी 1.6)। 2012-13 और 2013-14 में नियत पूंजी निर्माण में कमी के बावजूद, उच्चतर विकास दर प्राप्त करने का यह एक कारण

सारणी 1.12 : निवेश का क्षेत्र-वार संवितरण

क्षेत्र	स.घ.उ. के अनुपात में जीसीएफ (%)		
	2011-12	2012-13	2013-14
कृषि और सहबद्ध	3.1	2.6	2.5
उद्योग	13.5	12.9	11.7
विनिर्माण	7.1	6.9	6.0
अन्य औद्योगिक क्षेत्र	6.4	6.0	5.8
सेवाएं	19.5	18.0	17.1

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : इसमें मूल्यवान वस्तुएं और निधियों के प्रवाह से समायोजन कारक शामिल नहीं है तथा इसलिए जीसीएफ के साथ मेल नहीं खाएंगे।

हो सकता है। सारणी 11 दर्शाती है कि सभी प्रमुख क्षेत्र पूंजी निर्माण की दर में कमी द्वारा प्रभावित हुए हैं।

योजित सकल कीमत में कारक शेयर

1.33 स.घ.उ. की आय अवधारणा की तर्ज पर, किसी वर्ष में आधार मूल्यों पर योजित सकल कीमत को कर्मचारियों को मुआवजा (सीई), प्रचालन अधिशेष (ओएस) का योग/स्व-रोजगारों में लगे व्यक्तियों की मिश्रित आय (एम आई), नियत पूंजी का मुआवजा (सीएफसी) और उत्पादन पर सब्सिडियों के निवल के करों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सीई क्षेत्र में संदत्त मजदूरी और वेतनों की

सारणी 1.13 : स.घ.उ. के आय संघटक और आय तथा नियोजन शेयर

क्षेत्र	जीवीए में सीई	जीवीए में ओएस और एमआई	जीवीए में सीएफसी	क्षेत्र में जीवीए का हिस्सा	नियोजन शेयर
	औसत 2011-13				2011
कृषि और सहबद्ध	**15.3**	**81.6**	**6.6**	**18.1**	**48.9**
उद्योग	**35.7**	**49.1**	**14.6**	**31.9**	**24.3**
खनन और उत्खनन	23.9	62.5	12.8	3.0	0.5
विनिर्माण	23.6	58.4	17.0	17.8	12.6
विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	31.7	36.5	34.1	2.3	0.5
निर्माण	65.2	29.1	5.1	8.8	10.6
सेवा क्षेत्र	**38.9**	**50.0**	**10.4**	**50.0**	**26.9**
व्यापार, होटल और रेस्तंरा	23.5	69.9	5.2	11.4	11.0
परिवहन, भंडारण और संचार	37.9	49.8	15.0	6.6	4.8
वित्तीय, स्थावर भू-संपदा और व्यवसाय सेवाएं	26.1	61.4	10.8	19.4	2.3
समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	72.7	14.9	12.3	12.7	8.7
कुल	**33.6**	**55.5**	**11.1**	**100.0**	**100**

स्रोत : सीएसओ।

संयुक्त कीमत है। इसमें नियोजक द्वारा किए गए सामाजिक अंशदान शामिल हैं। यह जीवीए में कर्मचारियों के हिस्से को प्रदर्शित करती है। संगठित क्षेत्र में, ओएस योजित निवल कीमत और कर्मचारियों के मुआवजे के बीच अंतर है। गैर-संगठित क्षेत्र जो लेखों का अनुरक्षण नहीं करता है अथवा स्व-नियोजित श्रम द्वारा पूर्णतया प्रबंधन किया जाता है में अनिगमित उद्यमों और घरेलू उद्योगों के विद्यमान होने के परिणामस्वरूप, योजित निवल मूल्य (एनवीए) को श्रमिकों और उद्यमियों की आय के रूप में पृथक् नहीं किया जा सकता है। इससे लेखा पूर्ण करने के लिए 'स्वनियोजित की मिश्रित आय' कही जाने वाली नई मद की शुरुआत हुई (सारणी 1.13)।

1.34 कृषि क्षेत्र में, सीई केवल भाड़े के श्रमिकों की मजदूरी के हिस्से को प्रदर्शित करता है और इसलिए अपने खेतों में/उनके द्वारा भाड़े पर लिए गए खेतों में काम कर रहे किसानों के कुल प्रतिफल एमआई का हिस्सा बनते हैं। इसलिए, कृषि में रोजगार के हिस्से को कृषि में सीई से जोड़ना कठिन है। विनिर्माण और कतिपय सेवाओं में असंगठित खंड की विशाल उपस्थिति उनके रोजगार हिस्सों और जीवीए अनुपातों में सीई के बीच तालमेल बिठाने के लिए भी कठिनाई उत्पन्न करती है। यह उल्लेखनीय है कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा अपने जीवीए हिस्से से उच्चतर है, और यह जीवीए अनुपात में क्षेत्र के सीई में प्रतिबिम्बित होता है। कृषि के अलावा, निर्माण केवल ऐसा क्षेत्र है जिसका रोजगार हिस्सा जीवीए हिस्से से उच्चतर है। 2014-15 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, निर्माण में विकास दर क्रमिक रूप से बढ़ रही है जो रोजगार सृजन के लिए शुभ संकेत है।

1.35 सेवा क्षेत्र गतिविधियों में, असंगठित खंड की तुलनात्मक रूप से कम उपस्थिति वाले दो क्षेत्रों में वित्तीय, स्थावर भू-संपदा और व्यवसाय सेवाएं और समुदाय, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं हैं। अपने जीवीए और रोजगार हिस्सों में प्रतिकूलता के साथ सुसंगति के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जीवीए के अनुपात में सीई बहुत अलग है। समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में सरकारी उपस्थिति की प्रधानता है।

प्रतिव्यक्ति आय

1.36 2012-13 से 2013-14 के दौरान, नई श्रृंखला (उपर्युक्त सारणी) के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि अर्थात् 4.3 प्रतिशत, पुरानी श्रृंखलाओं द्वारा प्रस्तुत की गई 2.4 प्रतिशत की तदनुरूप वृद्धि से काफी अधिक है।

1.37 विकास, बचतों और निवेश, आदि के रूझानों का विश्लेषण करने के पश्चात् राजकोषीय स्थिति, भुगतान संतुलन, कीमतों, मौद्रिक प्रबंधन, आदि से संबंधित कतिपय अन्य महत्वपूर्ण वृहत-मानकों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

सरकारी वित्त

1.38 2013-14 में, राजकोषीय औचित्य नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ सरकार के अतिसक्रिय नीतिगत निर्णयों से वर्ष के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य के वर्षांत निष्पादन में सुधार हुआ। 2014-15 के प्रथम नौ माह आर्थिक सहायता के दौर में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का साक्षी रहा; संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रारम्भ की गई है; नई घरेलू गैस मूल्य निर्धारण नीति अनुमोदित की गई है और डीजल की कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। राजकोषीय समेकन का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यय सुधारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जांच पड़ताल करने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग गठित किया गया है। यह अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय की आबंटनात्मक और प्रचालन संबंधी दक्षताओं की समीक्षा करेगा।

1.39 अनंतिम लेखों के अनुसार, 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत के बजट अनुमान के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत रहा था। 2014-15 में, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः 5,31,177 करोड़ (जीडीपी का 4.1 प्रतिशत) और 3,78,348 करोड़ (जीडीपी का 2.9 प्रतिशत) के रूप में बजट विहित थे।

सारणी 1.14 : प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय

	(₹)				वृद्धि (प्रतिशत में)		
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
वर्तमान मूल्यों पर	64316	71593	80388	88533	11.3	12.3	10.1
स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	64316	66344	69959	74193	3.2	5.4	6.1

स्रोत : सीएसओ।

1.40 2014-15 के लिए बजट आकलन (बीई) का उद्देश्य जीडीपी अनुपात में कुल व्यय के 13.9 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी के लिए कर और जीडीपी में ऋण भिन्न प्राप्ति का क्रमश: 10.6 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करना है। सकल कर राजस्व की परिकल्पित वृद्धि संशोधित आकलन 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से अधिक और अनंतिम वास्तविक (पीए) 2013-14 में 19.8 प्रतिशत से अधिक रही। संशोधित आकलन 2013-14 और अनंतिम वास्तविक 2013-14 की तुलना में बजट अनुमान 2014-15 में कुल व्यय के क्रमश: 12.9 प्रतिशत और 14.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था।

1.41 महालेखा नियंत्रक द्वारा, अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के लिए, जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के वित्तियन संबंधी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष में उसी अवधि की तुलना में सकल कर राजस्व वृद्धि 7 प्रतिशत रही तथा यह अप्रैल-दिसम्बर, 2014 में बजट आकलन का 58.3 प्रतिशत है। अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान कर भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्ति और लाभांश तथा लाभ में बढ़ोत्तरी के कारण गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 27.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों में, मुख्यत: विनिवेश प्राप्तियों में कमी के कारण दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, अत्यधिक कमी आई, क्योंकि 58425 करोड़ की बजटीय धनराशि का केवल 1952 करोड़ की उगाही हुई है। अनेक विनिवेश प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं और वित्त वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में राजस्व आने की आशा है।

1.42 केन्द्रीय सरकार के लेखों के पक्ष में, अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान उल्लेखनीय रूझानों में गत वर्ष उसी अवधि के विपरीत योजना तथा योजना भिन्न व्यय वृद्धि में कमी आना शामिल है। खाद्यान्न सब्सिडी (21,807 करोड़ रुपए) और उर्वरक सब्सिडी (6,620 करोड़ रुपए) में बढ़ोतरी के कारण अप्रैल-दिसम्बर, 2013 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान बड़ी सब्सिडियों में वृद्धि हुई है। 2014-15 में अब तक का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम ईंधन मूल्य निर्धारण सुधारों तथा पेट्रोलियम उत्पादों की वैश्विक स्तर पर कीमतें कम होने के कारण 2013-14 में उसी अवधि की तुलना में पैट्रोलियम की सब्सिडी में 4,908 करोड़ रुपए की कमी आना है।

1.43 वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में बजट आकलन का 100.2 प्रतिशत पर का राजकोषीय घाटा पांच वर्ष के औसत 77.7 प्रतिशत से बहुत अधिक है। अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के संबंध में राजस्व घाटा बजट आकलन का 106.2 प्रतिशत आंका गया है तथा यह पांच वर्ष के 81.4 के औसत से काफी अधिक है।

कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन

1.44 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) (आधार वर्ष 2004-05 = 100) के दृष्टिगत मापी गई शीर्षस्थ मुद्रास्फीति जो 2011-13 के दौरान लगभग 6-9 प्रतिशत पर लगातार उच्च रही थी वह खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों में गिरावट आने पर 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में कुछ कम होकर औसतन 3.4 प्रतिशत रह गई। 2014-15 की प्रथम तिमाही में, थोक मूल्य सूचकांक आधारित शीर्ष मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत रही। इसका मुख्य कारण खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों का लगातार उच्च रहना था। 2014-15 की दूसरी और तीसरी तिमाही में, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर क्रमश: 3.9 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत रह गई। थोक मूल्य सूचकांक में शीर्ष मुद्रास्फीति जनवरी 2015 में 0.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के रूप में दर्ज हुई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित खाद्यान्न की मुद्रास्फीति (भार: 24.3 प्रतिशत), जो 2013-14 के दौरान 9.4 प्रतिशत पर उच्च रही थी, उसमें दिसम्बर, 2013 (मार्च, 2013 को छोड़कर) से सब्जियों की कीमतों में तेजी से गिरावट और अनाजों, अंडा, गोश्त और मछली की कीमतों के कुछ कम होने के बाद अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान कुछ कमी आई। चूंकि थोक मूल्य सूचकांक में ईंधन का अत्यधिक महत्व है। अत: ईंधन की कीमतें कम होने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (आधार वर्ष 2010 = 100) की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में तेजी से कमी आई। विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति 2013-14 से संकुचित सीमा के भीतर बनी रही। आधारवर्ष 2012 पर आधारित संशोधित सीपीआई (नई शृंखला) के अनुसार, शीर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी 2015 में 5.1 प्रतिशत पर रही।

1.45 2012-13 और 2013-14 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक (संयुक्त) (आधार वर्ष 2010 = 100) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति लगातार 9-10 प्रतिशत के बीच स्थिर रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की तरह, खाद्यान्न और मृदु पेयों तथा तम्बाकू; ईंधन और प्रकाश तथा अन्य जैसे सभी तीन बड़े उप-समूहों में मुद्रास्फीति में कुछ गिरावट के साथ, 2014-15 की दूसरी तिमाही से उपभोक्ता

सारणी 1.15 : थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2010 = 100) व्यापक समूहों में तिमाही वार मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	भार	2013-14				2014-15		
		ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3 (अ)
सामान्य	**100.0**	**9.5**	**9.7**	**10.4**	**8.4**	**8.1**	**7.4**	**5.0**
I. खाद्यान्न और मृदुपेय और तम्बाकू	49.7	11.0	11.1	12.9	9.2	8.9	8.6	4.8
II. ईंधन और प्रकाश	9.5	8.4	7.9	7.0	6.3	5.2	4.0	3.4
III. अन्य	40.8	7.9	8.2	8.0	7.9	7.6	6.7	5.5
खाद्यान्न (सीएफपीआई)	42.7	11.1	11.4	13.6	9.3	9.1	8.8	4.5
महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति (खाद्यान्न-भिन्न ईंधन-भिन्न)	42.9	8.0	8.2	8.1	8.0	7.7	6.8	5.7

स्रोत : सीएसओ। अ : अनंतिम।

मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में भी कुछ कमी आई है। 2014-15 की तीसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) आधारित मुद्रास्फीति कम होकर 5 प्रतिशत रह गई (सारणी 1.15)।

1.46 वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में प्रत्याशित से अधिक तेजी से कमी आई। वैश्विक कारक, अर्थात् कच्चे तेल के मूल्यों में निरन्तर कमी, व्यापार किए जाने वाले सामान, खासकर खाद्य तेलों और कोयले की कीमतों में भी वैश्विक स्तरों पर कमी से उच्च स्तर की मुद्रास्फीति को संयत करने में मदद मिली। सख्त मौद्रिक नीति मांग के दवाब को नियंत्रण में रखने, किसी विदेशी आघात से निपटने को बफर सृजन और रुपए के मूल्य में घट-बढ़ को नियंत्रित रखने में सहायक हुई। गत एक वर्ष के दौरान, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा, इसका भी मुद्रास्फीति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। मजदूरी दर वृद्धि के संयत रहने से प्रोटीन आधारित वस्तुओं पर मांग के दवाब में कमी आई। मूलभूत प्रभाव ने भी उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति में कमी लाने में योगदान दिया।

मौद्रिक गतिविधियां

1.47 भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने वर्ष के दौरान जनवरी तक नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी। मुद्रास्फीति संबंध ी परिस्थितियों के सुगम रहने से, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2015 में नीतिगत रेपो दर में 25 आधारभूत अंकों की कटौती करके इसे 7.75 प्रतिशत तक रखकर मौद्रिक नीति स्वरूप में गिरावट लाने के संकेत दिए। तदुपरांत भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 आधार अंक द्वारा सांविधिक नकदी अनुपात को भी निवल मांग तथा मियादी देयताओं के 22.5 प्रतिशत से घटाकर 22.0 प्रतिशत कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2014 से नीतिगत संचार के लिए मामूली एंकर के उपाय के रूप में नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सम्मिलित) को अपनाया।

1.48 नकदी प्रबंधन प्रचालनों में लोचनीयता, पारदर्शिता और संभाव्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 2014 में अपने नकदी प्रबंधन ढांचे को संशोधित किया। अबतक, 2014-15 के दौरान, अल्पकालिक तंग परिस्थितियों के सिवाय, नकदी संबंधी परिस्थितियां मोटे तौर पर संतुलित रहीं। संशोधित नकदी प्रबंधन ढांचा 14 दिवसीय सावधि रेपो नीलामियों तथा एक दिनी परिवर्तनीय रेपो नीलामियों में भारित औसत कटौती दरों को रेपो रेट के समीप रखने में सहायक हुआ।

वैदेशिक क्षेत्र

1.49 2013-14 में आरम्भिक अस्तव्यस्तता के पश्चात्, वर्ष के लिए समग्र परिणाम पुष्ट रहा। इसका कारण वे नीतियां रहीं जिन्हें असाधारण स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किया गया था। चालू वित्त वर्ष के जरिए संपुष्ट वैदेशिक क्षेत्र परिणाम की निरन्तरता से सोने पर से प्रतिबंध हटाने में सुगमता हुई और कच्चे पेट्रोलियम का वैश्विक स्तर पर कम कीमतों के चलते डीजल मूल्य निर्धारण में सुधार लाने में सहायता मिली। वैश्विक कच्चे पेट्रोलियम के मूल्यों के जरिए घरेलू डीजल के मूल्यों में कमी न आना दुतरफा घाटों के उच्च स्तर में एक महत्वपूर्ण कारक रहा। आगे चलकर, विदेशी परिणाम की संपुष्टता स्थायी सुधार एंकर पर निर्भर करेगी।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

1.50 गत दस वर्षों में, भारत का व्यापारिक माल व्यापार (सीमाशुल्क आधार पर), 2004-05 में 195.0 बिलियन अमरीकी डालर से 2013-14 में बढ़कर 764.6 बिलियन अमरीकी डालर तक कई गुणा बढ़ गया। इससे 2004 में वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत से सुधर कर 2013 में 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत तक होने में मदद मिली। 2004 में प्रमुख निर्यातकों और आयातकों में इसका स्थान 30 और 23 से सुधरकार 2013 में क्रमशः 19 और 12 हो गया।

1.51 2013-14 में 4.7 प्रतिशत तक वृद्धि होने के पश्चात्, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में भारत का व्यापारिक माल निर्यात 2.4 प्रतिशत की संयत वृद्धि के साथ 265 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। 2013-14 के दौरान, भारत का व्यापारिक माल आयात 8.3 प्रतिशत तक कम होकर 450 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में, आयात 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में 375.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.2 प्रतिशत बढ़कर 383.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्टस (पीओएल) आयात मूल्य, जो 2013-14 में भारत के कुल आयात का 36.6 प्रतिशत बैठता था, वह कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमी आने के परिणामस्वस्प, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी), में 7.9 प्रतिशत घट गया। 2012-13 और 2013-14 में पीआएल की आय वृद्धि क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत रही। पर्याप्त पास थ्रू की अपेक्षा कम आपूर्ति के कारण, चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही तक पीओएल आयात स्तर उच्च बना रहा। 2014-15 की पहली तिमाही कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य (ब्रेन्ट) 109.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल से घटकर तीसरी तिमाही में 76.0 अमरीकी डालर प्रति बैरल रह गया जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में पीओएल के आयात मूल्य में 7.9 प्रतिशत की कमी आई।

1.52 भारत के कुल आयात में सोने और चांदी के आयात का हिस्सा 2012-13 में 11.4 प्रतिशत और 2013-14 में 7.4 प्रतिशत रहा। सोने और चांदी का आयात, जिसमें 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 9.6 प्रतिशत और 40.4 प्रतिशत की कमी आई थी उसमें 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूंजीगत माल के आयात में 2011 से निरंतर गिरावट आ रही थी। पीओएल भिन्न और सोना तथा चांदी भिन्न आयात जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु आवश्यक आयात को काफी हद तक प्रतिबिम्बित करता है। इसमें 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने के उपरान्त 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 7.8 प्रतिशत वृद्धि हुई;

1.53 हालिया वर्षों में विनिर्मित सामानों का वृहत निर्यात 63 प्रतिशत से अधिक बैठता था, इसके बाद 20 प्रतिशत हिस्से के साथ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों (कोयला सहित) और 13.7 प्रतिशत के हिस्से के साथ कृषि और संबद्ध उत्पादों का स्थान आता है। 2011-12 में 300 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने के पश्चात् निर्यात वृद्धि दरों में उल्लेखनीय गिरावट आई है जो कमोवेश एक वैश्विक घटना है क्योंकि 2011 से यूरोजोन संकट के चलते वैश्विक व्यापार खंडों में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। पेट्रोलियम और कृषि तथा संबद्ध उत्पादों की निर्यात वृद्धि जो गत चार वर्ष के दौरान, सकारात्मक रही थी, 2014-15 (जनवरी-अप्रैल) में नकारात्मक हो गइ। रत्न और आभूषण निर्यात जिसमें 2012-13 और 2013-14 में गिरावट का रूझान प्रदर्शित हुआ था, उसमें 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माल के मामले में 2012-13 से निर्यात में निरंतर कमी आती रही है। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, परिवहन उपस्कर; मशीनरी और कलपुर्जों; धातु निर्मित सामानों और तैयार परिधानों जैसे कतिपय क्षेत्रों में निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में समुद्रीय उत्पादों और चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित उत्पादों में तुलनात्मक रूप से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।

1.54 हालिया वर्षों में, भारतीय व्यापार में महत्वपूर्ण बाजार विविधता रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यूरोजोन में काफी हद तक कमजोरी के कारण मंद वैश्विक मांग से निपटने में मदद मिली है। क्षेत्र-वार यूरोप और अमेरिका का भारतीय निर्यात हिस्सा कुछ वर्षों से 2004-05 में क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में क्रमशः 18.6 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत एशिया तथा अफ्रीका को भारतीय निर्यात का हिस्सा 2004-05 में क्रमशः 47.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत हो गया है।

1.55 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में, व्यापार घाटा 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में 116.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में मामूली अर्थात् 1.6 प्रतिशत बढ़कर

118.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी), में निर्यात (2.4 प्रतिशत) और आयात (2.2 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष) में अल्प वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में 1.9 बिलियन अमरीकी डालर की सीमांत वृद्धि हुई।

भुगतान संतुलन

1.56 आयात और इसके वित्तपोषण के उच्च स्तरों के कारण 2011-12 और 2012-13 में चालू खाता घाटा के बढ़ने के अदृश्य आयात-निर्यात खाते में निवेश आय के रूप में अपेक्षाकृत अधिक राशि के बहिर्वाह के दृष्टिगत निहितार्थ रहे हैं। केड के स्तर के अनुपात के रूप में ऐसा बहिर्वाह 2007-08 में 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 72.6 प्रतिशत हो गया। केड में कमी की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह थी कि इसके पूर्ण वित्तपोषण से भी, निवेश के आय-व्यय के माध्यम से केड के स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

1.57 2014-15 की प्रथम छमाही में, भारतीय वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति हितकर और आरामदायक रही। दो महत्वपूर्ण गतिविधियां (i) अदृश्य आयात-निर्यात में सीमित वृद्धि के साथ-साथ कम व्यापार घाटा, जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा कम रहा और (ii) अपेक्षाकृत अधिक पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा समर्थित पूंजी अंतर्वाह में वृद्धि, रही।

1.58 चालू खाता घाटे के वित्तपोषण की जरूरत से पूंजीगत अंतर्वाह अधिक हुआ और परिणामत: विदेशी मुद्रा भंडार की संचित राशि में वृद्धि हुई। चालू खाता घाटा 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 2013-14 की इसी अवधि में 26.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 17.9 बिलियन अमरीकी डालर रखा गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में, चालू खाता घाटा 2013-14 की पहली छमाही में 3.1 प्रतिशत से घटकर 2014-15 की पहली छमाही में 1.9 प्रतिशत रह गया। निवल वित्तीय प्रवाह 2013-14 की पहली छमाही में 16.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2014-15 की पहली छमाही में 36.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा। निवल विदेशी निवेश 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 7.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 38.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल वैदेशिक वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) भी 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से सुधरकर 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 3.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इसी अवधि के दौरान निबल बैंकिंग पूंजी 11.5 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर (-) 0.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। चालू खाता घाटे की तुलना में निवल पूंजीगत प्रवाह उच्चतर रहने से भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार (भुगतान संतुलन आधार पर) 2013-14 की पहली छमाही में 10.7 बिलियन अमरीकी डालर की कमी के विपरीत 2014-15 की पहली छमाही में बढ़कर 18.1 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर हो गया।

1.59 चालू खाता घाटे वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। 6 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, 330.2 बिलियन अमरीकी डालर के भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से 305.0 बिलियन अमरीकी डालर की धनराशि वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां शामिल हैं जो कुल राशि की लगभग 92.5 प्रतिशत बैठती हैं। 2014-15 की पहली छमाही में आरक्षित निधि में बढ़ोतरी के साथ, आरक्षित निधि आधारित सभी परम्परागत वैदेशिक क्षेत्र के कमजोरी संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, आरक्षित निधि के लिए अल्पावधि विदेशी ऋण का अनुपात मार्च, 2014 के अन्त में 29.3 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2014 के अन्त में 27.5 प्रतिशत रह गया और आयात हेतु आरक्षित निधि का दायरा भी मार्च, 2014 के अन्त में 7.8 माह से बढ़कर सितम्बर, 2014 में 8.1 माह हो गया।

1.60 इक्विटी और बांड बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के व्यापक अंतर्वाह के कारण वर्ष के दौरान रूपया-अमरीकी डालर की विनिमयदर मोटे तौर पर स्थिर रही। यूरोप और जापान में कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण के चलते, अमरीकी डालर की तुलना में यूरो और येन की परस्पर लेन-देन की गतिविधियों के साथ कमोवेश सितम्बर, 2014 से यूरो और येन की तुलना में रुपये की स्थिति में सुधार हुआ। बिंदु पर बिंदु आधार पर रुपये की स्थिति में 28 मार्च, 2014 को 60.10 रुपये प्रति अमरीकी डालर से 30 जनवरी, 2015 को 61.76 रुपये प्रति अमरीकी डालर अर्थात 2.7 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। 30 दिसम्बर, 2014 को रुपया 63.75 रुपये प्रति अमरीकी डालर के निम्नतम स्तर से 19 मार्च, 2014 को 58.43 रुपये प्रति अमरीकी डालर की बुलंदी पर पहुंच गया।

विदेशी ऋण

1.61 भारत का विदेशी ऋण स्टॉक, मार्च, 2014 के अंत में अपने स्तर से सितम्बर, 2014 के अंत में 13.7 बिलियन अमरीकी डालर (3.1 प्रतिशत) बढ़कर 455.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। विदेशी ऋण में बढ़ोत्तरी का कारण उच्चतर दीर्घावधि ऋण खासकर वाणिज्यिक उधार और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियां रहीं। भारत के

विदेशी ऋण की परिपक्वता पृष्ठभूमि से दीर्घावधि उधारों के वर्चस्व का संकेत मिलता है। सितम्बर, 2014 के अन्त में दीर्घावधि ऋण मार्च, 2014 के अंत में 79.8 प्रतिशत की तुलना में कुल विदेशी ऋण का 81.1 प्रतिशत बैठता है। भारत का विदेशी ऋण नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रहा जैसाकि 2013-14 में विदेशी ऋण के अनुपात जीडीपी का 23.5 प्रतिशत और ऋण सेवा अनुपात 5.9 प्रतिशत से संकेत मिला। भारत सरकार की विवेकशील विदेशी ऋण प्रबंधन नीति, विदेशी ऋण की आरामदायक स्थिति को बनाए रखने में सहायक हुई है।

2015-16 हेतु नज़रिया

1.62 भारत की वृहत आर्थिक परिस्थिति में वर्तमान वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सुधार आया है। राष्ट्रीय लेखाओं की जारी हुई नई श्रृंखला से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अतीत की तुलना में उम्मदी से काफी बेहतर चल रही है। वैश्विक मांग की परिस्थिति में आयी गिरावट के मुकाबले सेवाओं तथा विनिर्माण क्षेत्र में हो रही निरन्तर तेज़ी भारत की घरेलू मांग के मज़बूत होने की ओर संकेत करती है। घरेलू मांग में आए उछाल का कारण खपत है। निवेश गतिविधि, जो कि धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है; को मजबूत आधार प्रदत्त किए जाने की आवश्यकता है। आनेवाले वर्षों में इस वृद्धि को और ष्अधिक मज़बूत करने के लिए वर्तमान में दिख रहे बाह्य क्षेत्र के हितकर परिणाम के उलटफेर के साथ-साथ बचत-निवेश की गतिशीलता भी महत्वपूर्ण होगी। इसकी कुंजी, बेहतर मूल्य पर बचतों के प्रति अनुक्रिया, वित्तीय बाजार स्थिरता, विशेषकर महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक निवेश और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार प्रयास होंगे।

1.63 आपूर्ति के संबंध में, निर्माण और खनन गतिविधियों में अस्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति को लेकर चिंता हैं जिनका निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। यह खासकर इन क्षेत्रों के मजबूत अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्क के मद्देनजर और भी अधिक महत्वपूर्ण है। खेती के क्षेत्र में अपेक्षाकृत मॉनसून की खराब स्थिति की वजह से नुकसान हुआ, किन्तु इसका अगले वर्ष असर पड़ने की कोई आशंका नहीं है। वर्धित मूल्य के अनुपात में उत्पादन द्वारा प्रस्तुत अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन की दर में सुधार तथा संबर्धानात्मक पूंजी उत्पादन अनुपात में गिरावट उत्पादन में संसाधन के बेहतर इस्तेमाल की ओर संकेत करते हैं।

1.64 वैश्विक रूप से, संयुक्त राज्य अमरीका आत्म विश्वास और दृढ़ता को प्रदर्शन करता है, जबकि चीन, रूस, यूरो क्षेत्र और जापान जैसी संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण कुछ अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चित संभावनाओं से जूझ रही है, जिसके कारण वैश्विक प्रगति और निवेश का नज़रिया प्रभावित होता है। तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण समग्र वैश्विक विकास और स्थिरता को प्रोत्साहन मिला है। साथ ही इससे तेल का निर्यात करने वाले देशों का भाग्य अंधकारमय हो गया है। इससे आर्थिक गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

1.65 तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के सामान्यतया कम रहने की संभावना सहित कीमत एवं बाह्य क्षेत्र परिदृश्य में सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में संयुक्त राज्य अमरीका की ब्याज दरों में वृद्धि से उत्पन्न हो सकने वाली अनिश्चितताओं तथा यूरो क्षेत्र के अन्दर ग्रीस में व्याप्त परिस्थितियों के बावजूद घरेलू वृहत आर्थिक मापदण्ड हेतु नजरिया सामान्यतया आशावादी है। उपर्युक्त को देखते हुए, तथा विश्व की अर्थव्यवस्था में सामान्य मॉनसून की बेहतर संभावनाओं को मानते हुए जो कि भारतीय उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को गति प्रदान कर सकती है; 2015-16 में लगभग 8.5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

क्षेत्र संबंधी गतिविधियां

कृषि

1.66 दसवीं योजना के दौरान, देश के सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 की कीमतों पर) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 19 प्रतिशत रहा। यह ग्यारहवीं योजना के दौरान घटकर 15.2 प्रतिशत रह गया। यह संक्रमण के दौरान अर्थव्यवस्थाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के विशिष्ट विगत प्रतिरूप के अनुसार है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने नौवीं योजना में 2.5 प्रतिशत, दसवीं योजना में 2.4 प्रतिशत और ग्यारहवीं योजना में 44.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.67 वर्ष 2013-14 के लिए, चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 264.8 मिलियन टन आंका गया है, जो गत वर्ष से 7.6 मिलियन टन अधिक तथा गत पांच वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के औसत उत्पादन की तुलना में 22.04 मिलियन टन अधिक है। कृषि मंत्रालय द्वारा 19 सितम्बर, 2014 को जारी किए गए अग्रिम आकलनों के अनुसार, 2014-15 के दौरान खरीफ में कुल खाद्यान्न उत्पादन 120.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2013-14 में 129.32 मिलियन टन तथा 2012-13 में 117.18 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था।

सारणी 1.16 : कृषि क्षेत्र : महत्वपूर्ण सूचकांक (वर्तमान कीमतों पर प्रतिशत)

वस्तु	2011-12	2012-13	2013-14
कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	18.4	18.0	18.0
फसलें	12.0	11.7	11.8
पशुधन	4.0	4.0	3.9
वानिकी और लॉगिंग	1.6	1.5	1.4
मत्स्य पालन	0.8	0.8	0.9
कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	8.6	7.7	7.9
फसलें	7.4	6.5	6.6
पशुधन	0.8	0.7	0.7
वानिकी और लॉगिंग	0.1	0.1	0.1
मत्स्य पालन	0.4	0.4	0.5
क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 की चालू कीमतों पर) में प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण	18.3	15.5	14.8

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

1.68 भारतीय कृषि के लिए कुछ चुनौतियां और नीतिगत सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- कृषि और खाद्यान्न क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, सिंचाई, उर्वरकों और मृदा परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं, पानी और वस्तुओं, भंडारागारों, शीतगृहों में व्यापक निवेश की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता को युक्तिसंगत बनाने और लाभार्थियों पर उन्हें बेहतर तरीके से लक्षित करने से सरकारी निवेश हेतु संसाधन सृजित होंगे।
- राज्यों के भीतर पैदावार में व्यापक भिन्नता होती है। विश्व के सर्वोतम देशों से अपने सर्वोत्तम राज्यों की तुलना करने पर इन राज्यों में भिन्न-भिन्न फसलों की पैदावार काफी कम है। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पैदावार के अन्तर को संभव सीमा तक कम करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरपूर गुंजाइश बनती है।
- सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर पैदावार में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि विस्तृत फसलदार क्षेत्र अभी भी असिंचित है। उत्पादन कार्य में बदलाव लाने के लिए, बुनियादी अनुसंधान में निवेश आवश्यक होगा।
- शांता कुमार समिति की अनुशंसाओं में खाद्यान्न नीति की भावी रूपरेखा से संबंधित उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। कृषि जिन्सों के लिए राष्ट्रीय कॉमन बाजार के सृजन हेतु राज्यों को तैयार करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।
- विद्युत और पानी हेतु उपयोगकर्ता प्रभारों से छूट सहित, विभिन्न नीतियों से उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- किसानों को सक्षम अग्रिम मूल्य अन्वेषण कार्य सुलभ करने खोज उपलब्ध कराने और इन्हें मूल्य जोखिम से संरक्षित करने के लिए वायदा बाजार आयोग को मजबूत किया जाना चाहिए तथा बाजार को और अधिक कारगर ढंग से विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

औद्योगिक, कार्पोरेट तथा अवसंरचना संबंधी निष्पादन

1.69 2011-12 को आधार वर्ष मानकर, हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि 2004-05 के आधार वर्ष के साथ पूर्व के अनुमान से काफी अधिक बेहतर थी। गिरावट का रुझान घरेलू मांग में धीमेपन, मुद्रास्फीति दबावों, और निवेश लागतों में बढ़ोतरी तथा विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण था। इसके अतिरिक्त, 2013-14 में उद्योग में सकल पूंजी निर्माण में 1.4% वृद्धि का आशय है कि औद्योगिक वृद्धि विगत वर्ष में प्रारंभ हो चुकी थी।

1.70 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार औद्योगिक वृद्धि की तस्वीर इस बात की ओर संकेत करती है कि जो औद्योगिक उत्पादन 2011-12 से मंद रहा

था उसका रुझान 2014-15 में बिल्कुल पलट गया। अप्रैल-नवंबर 2014-15 में आईआईपी के उपभोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, बुनियादी वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि में विशिष्ट सुधार देखने को मिला। जबकि अंतर्वर्ती वस्तुओं में वृद्धि धीमी रही, अप्रैल-नवंबर 2014-15 में उपभोक्ता वस्तुओं में विशेषकर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में संकुचन के कारण संकुचन आया।

1.71 आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक पर आधारित अवसंरचना में वृद्धि अप्रैल-दिसंबर 2013-14 में 4.1% से थोड़ी सुधर कर 2014-15 की इसी अवधि में 4.4% हो गई। कोयला, बिजली और सीमेंट के निष्पादन में विशिष्ट सुधार देखने को मिला, स्टील और रिफाइनरी उत्पादों में क्रमशः 1.6% और 0.2% का कम सुधार हुआ जबकि कच्चा तेल, गैस और उर्वरकों में ऋणात्मक वृद्धि रही। परिवहन क्षेत्र में 2014-15 के प्रथम नौ महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेल भाड़ा (5.1%), घरेलू हवाई यात्री परिवहन (7.1%), अंतरराष्ट्रीय यात्री परिवहन (10.3%), अंतरराष्ट्रीय नौभार (8.3%), घरेलू नौभार (19.3%) और प्रमुख व छोटे बंदरगाहों पर सकल नौभार (6.8%) में सुधार हुआ।

1.72 बिक्री में वृद्धि और निवल लाभ के संदर्भ में निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों का कार्य-निष्पादन 2014-15 की प्रथम तिमाही में एकदम सुधरा हुआ प्रतीत हुआ। तथापि 2014-15 की दूसरी तिमाही के निष्पादन ने सतत् सुधार की आशाओं को धूमिल कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक की ऑर्डर बुक्स, माल सूची (इन्वेंटरीज़) और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 2014-15 की प्रथम दो तिमाहियों में क्षमता उपयोग में कोई दृष्टिगोचर सुधार नहीं है।

1.73 1000 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत की कुल 246 केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं में से 124 में नवीनतम कार्यक्रम के कारण विलंब हुआ और 24 परियोजनाओं में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पिछले महीने की रिपोर्ट (अक्तूबर 2014 के लिए फ्लैश रिपोर्ट) में समापन की तारीख के विपरीत अतिरिक्त विलंबों की रिपोर्ट मिली है।

1.74 खनन क्षेत्र के अतिरिक्त सभी अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में 2013-14 की तुलना में 2014-15 में ऋण की वृद्धि में मंदी देखी गई। 2014-15 में 13.3 प्रतिशत पर विनिर्माण क्षेत्र में ऋण प्रवाह की वृद्धि वर्ष 2013-14 में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम रही। वर्ष 2014-15 में रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्रों में ऋण की वृद्धि में एकदम गिरावट देखी गई।

1.75 अप्रैल नवंबर 2014-15 के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कुल अंतर्वाह (ईक्विटी अंतर्वाह, पुनःनिवेशित अर्जन और अन्य पूंजी) 27.4 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह 18.9 बिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल 2000 से नवंबर 2014 के बीच कुल संचयी एफडीआई अंतर्वाह 350.9 बिलियन अमरीकी डालर था। सेवाएं, निर्माण, दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दवा और औषधि, वाहन उद्योग, रसायन, विद्युत इत्यादि में कुल अंतर्वाहों का असंगत रूप से एक बड़ा भाग आकर्षित हुआ।

सेवा क्षेत्र

1.76 भारत का सेवा क्षेत्र 2014-15 में जीडीपी वृद्धि में 72.4 प्रतिशत की भागीदारी निभाते हुए आर्थिक वृद्धि का बड़ा प्रेरक बना रहा। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2012-13 में 8.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 9.1 प्रतिशत और 2014-15 में और बढ़ते हुए 10.6 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि प्रमुखतः वित्तीय, भूसंपत्ति और पेशेवर सेवाओं में पिछले वर्ष 7.9 प्रतिशत की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 7.9 प्रतिशत की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और संबद्ध सेवाओं में वृद्धि वर्ष 2013-14 में 11.1 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2014-15 में 8.4 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2015 के प्रारंभिक महीनों के लिए उपलब्ध आंकड़े व्यवसायिक क्रियाकलाप में विस्तार के साथ सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी की ओर संकेत करते हैं जैसाकि सेवाओं के पीएमआई आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। इस वृद्धि संवेग के 2015-16 में भी जारी रहने की आशा है।

1.77 सेवा क्षेत्र भारत के अधिकांश राज्यों में भी प्रभावी क्षेत्र रहा है क्योंकि वर्ष 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेवाओं का हिस्सा लगभग सभी राज्यों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक रहा था। इस क्षेत्र ने एफडीआई अंतर्वाहों, निर्यातों और रोजगार में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। पिछले 12 वर्षों के दौरान, 8.7 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि औसत (सीएजीआर) के साथ, भारत का सेवा क्षेत्र मात्र चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक बढ़ता सेवा क्षेत्र था, जहां चीन के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.7 प्रतिशत थी। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में, भारत की इस अवधि के दौरान 20 प्रतिशत की उच्चतम मिश्रित वार्षिक वृद्धि औसत (सीएजीआर) थी। भारत की वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष

2013 में 3.2 प्रतिशत हो गई। 2013 में अग्रणी निर्यातकों में इसकी छठी रैंक थी। 2014-15 के पूर्वार्द्ध में, सेवाओं के निर्यात 3.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 75.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए और सेवाओं का आयात 5.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ 39.9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, जिसके परिणामत: निवल सेवा वृद्धि केवल 2.4 प्रतिशत रही। निर्यातों में मूल्यवर्द्धित सेवाओं का हिस्सा भी बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सेवाओं पर हुई बातचीत में, भारत बहुत सक्रिय है और हाल ही में इसने अल्प विकसित देशों के लिए और अधिक उदार पेशकश की हैं।

1.78 उप क्षेत्रों में, कंप्यूटर और संबद्ध सेवाएं भारत के स.घ.उ. में 3.3 प्रतिशत के हिस्से के साथ वर्ष 2013-14 में 14.4 प्रतिशत बढ़ी हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, देश की कुल आय में पर्यटन और रोजगार की भागीदारी क्रमश: 6.9 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत थी। 2014 में, विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा अर्जन में क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बैंकिंग और बीमा

1.79 इस वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता कुछ दबाव ग्रस्त रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक पेशगियां (एनपीए) कुल सकल पेशगियों की प्रतिशतता के रूप में मार्च, 2014 की 4.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2014 में 4.5 प्रतिशत हो गई। दबाव ग्रस्त पेशगियां मार्च और सितंबर 2014 के बीच, कुल पेशगियां की 10.0 प्रतिशत से बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए के मामले के समाधान हेतु कोई उपाय किए।

1.80 2014-15 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाओं की विकास दर मुख्यत: बुनियादी प्रभाव अर्थात पिछले वर्ष सितंबर-नवंबर के दौरान एनआरआई जमाओं में अभिवृद्धि के कारण और इस वर्ष के दौरान निम्न जमाओं के कारण, दिसंबर तक गिरी। गैर-खाद्य साख की विकास दर में भी गिरावट आई।

1.81 वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) 28 अगस्त, 2014 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं में सार्वभौमिक अभिगम्यता की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम को भी बड़ा बल मिलने की आशा है।

1.82 वर्ष 2014-15 में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में अन्य सुधारात्मक पहलें देखी गई, जिनमें बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने के लिए सरकार के हिस्से को 52 प्रतिशत तक कम करते हुए बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देना और बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के लिए अध्यादेश को अधिसूचित करना शामिल है।

1.83 इस वर्ष के दौरान इक्विटी बाजार निरंतर अच्छा निष्पादन करते रहे। बेंचमार्क सूचकांक, बीएसई सेन्सेक्स और निफ्टी में चाल? वर्ष में सामान्य बढ़ोतरी का रुझान देखा गया। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों के कार्यचलन में सुधार लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा कारपोरेट अभिशासन मानदंडों में सुधार लाने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) विनियमन रूपरेखा की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए थे।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

1.84 2020 तक भारत के विश्व का सबसे युवा राष्ट्र होने की संभावना है। इससे भारत को बड़े अवसरों के साथ साथ विपुल चुनौतियां भी मिलेंगी। भारत की कुल जन्म-दर (टीएफआर) निरंतर कम हो रही है जो कि अभी 2.3 है; हालांकि राज्यवार विषमता अभी विद्यमान है। 2013 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार, 0-14 आयु-वर्ग की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1971 से 1981 के दौरान 41.2 से 38.1 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट के साथ 1991 से 2013 के दौरान 36.3 से 28.4 प्रतिशत रह गई है, जबकि आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष), 1971 से 1981 के दौरान 53.4 से 56.3 प्रतिशत और 1991 से 2013 के दौरान 57.7 से 63.3 प्रतिशत बढ़ी। बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में सतत् गिरावट चिंता की बात है। बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण और शिक्षा के संवर्द्धन के लिए एक नई स्कीम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जनवरी 2015 में, प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक मानसिकता बदलना और बेहतर जागरूकता लाने पर लक्षित एक व्यापक जन-अभियान के माध्यम से घटते सीएसआर के मुद्दे का समाधाान करना है।

1.85 वर्ष 2020 में, भारत की जनसंख्या की औसत आयु विश्व में न्यूनतम लगभग 29 वर्ष होना संभावित है। परिणामत, जबकि 2020 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 56 मिलियन युवा जनसंख्या की कमी आना संभावित है, भारत ऐसा अकेला देश होगा जिसमें 47 मिलियन युवा

अधिशेष होंगे। इन युवाओं का स्वस्थ, उपयुक्त रूप से शिक्षित और उचित रूप से कुशल होना आवश्यक है ताकि वे अर्थव्यवस्था में अपनी पूर्ण भागीदारी दे सकें।

1.86 **शैक्षिक चुनौतियां:** हालांकि साक्षरता (जनगणना 2011) का लक्ष्य केवल 73 प्रतिशत प्राप्त हुआ है, फिर भी महिला साक्षरता में विशिष्ट सुधार है। 80.9 प्रतिशत की पुरूष साक्षरता दर अब भी 64.6 प्रतिशत की महिला साक्षरता दर से ऊंची है परंतु पुरूष साक्षरता में 5.6 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि की तुलना में महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्कूलों में कुल नामांकन 2013-14 में घटा है; जबकि उच्च प्राथमिक नामांकन में वृद्धि हुई है। यह आयु ढांचे में जनसांख्यिकीय परिवर्तनो के अनुरूप है। तथापि, शिक्षा प्रणाली का समग्र मानक वैश्विक मानकों से बहुत नीचे है। शिक्षा रिपोर्ट का वार्षिक स्तर (एएसईआर) का अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि समस्त देश में, चाहे सरकारी हो या निजी स्कूल, अध्ययन के स्तरों में सुधार नहीं हुआ है। स्पष्टत:, नीतिगत सुझाव हैं कि ध्यान निर्विष्टियों से हटाकर परिणामों पर लगाया जाए तथा शिक्षा गुणवत्ता और कौशल विकास अवसंरचना के निर्माण पर बल दिय जाए। पढ़ने, लिखने और गणित में धाराप्रवाहिता के लिए आधार सृजित करने के लिए पढ़े भारत, बढ़े भारत की पहल इस दिशा में एक अच्छा कदम है।

1.87 **युवा वर्ग का कौशल विकास:** लेबर ब्यूरो रिपोर्ट, 2014 के अनुसार, भारत के औपचारिक रूप से कुशल श्रमबल का मौजूदा आकार छोटा है जो लगभग 2 प्रतिशत है; यह आंकड़ा दक्षिण कोरिया और जापान जैसे छोटे देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिनके आकड़े क्रमश: 96 प्रतिशत और 80 प्रतिशत हैं। कुल मिलाकर भारत में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 6.8 प्रतिशत व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं/प्राप्त कर रहे हैं। 2013 और 2022 के बीच की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्र में 120 मिलियन कुशल व्यक्तियों की वृद्धिक रूप की आवश्यकता है। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता का एक समर्पित विभाग सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल-निर्माण पर अब पुन: बल दिया गया है और इसे पुन:वरीयता दी गई है ताकि ग्रामीण निर्धन युवावर्ग की क्षमता का निर्माण किया जा सके। अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से नए कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं।

1.88 **रोजगार में धीमी वृद्धि:** चिंता का एक कारण रोजगार की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में गिरावट भी है जो कि 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 से 2011-12 के दौरान 0.5 प्रतिशत रह गई है जबकि इन्हीं दो अवधियों के दौरान श्रम बल में सीएजीआर क्रमश: 0.4 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत रही। 1999-2000 से 2004-05 के दौरान, श्रमशक्ति में 407.0 मिलियन से 469.0 मिलियन यानि 62.0 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि होने के मुकाबले में सामान्य स्थिति (यू एस) आधार पर रोजगार में 398.0 मिलियन से 457.9 मिलियन यानि 59.9 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 2004-05 से 2009-10 के दौरान हुई धीमी गति की प्रगति की अवधि के बाद, 2009-10 से 2011-12 के दौरान रोज़गार सृजन में तीव्र वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप कार्यबल में 13.9 मिलियन व्यक्ति जुड़े किन्तु यह वृद्धि श्रम शक्ति (14.9 मिलियन व्यक्ति) में हुई वृद्धि के बराबर नहीं थी। भारत में अच्छे रोज़गारों के सृजन की गति में प्रमुख बाधा कुल रोजगार में विनिर्माण का छोटा हिस्सा होना है। फिर भी, 68वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े विनिर्माण क्षेत्र में 2009-10 में 11 प्रतिशत से 2011-12 में 12.6 प्रतिशत होकर रोज़गार की वृद्धि के पुनर्विकास का संकेत देतेहैं। इस परिप्रेक्ष्य से सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यम (एमएसएमई) के विकास का संवर्द्धन महत्वपूर्ण है।

1.89 **श्रम सुधार:** श्रम कानूनों की बहुलता और उनकी अनुपालना में आने वाली कठिनाइयां औद्योगिक विकास में अवरोधक रही है। प्रणाली में अनुपालना को लाने तथा सुगमता से कारोबार करने को सुगम करने के लिए सरकार द्वारा श्रम सुधार संबंधी अनेक उपायों को लाया गया है।

1.90 **स्वस्थ भारत की ओर:** अक्तूबर, 2014 में आरंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) का लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच करने से मुक्त भारत बनाना है। इसके अलावा दिसम्बर, 2014 में शुरू किए गए इन्द्रधनुष अभियान के अंतर्गत 2020 तक ऐसे सभी बच्चों को सात बीमारियों के प्रतिरोधी टीके लगाए जाएंगे, जिन्हें ये टीके नहीं लगे हैं या इनमें से कुछ टीके लगे हैं। पूर्व आयुष विभाग (आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि और होमियोपैथी) को अब एक नए पूर्ण मंत्रालय के रूप में बदल दिया गया है।

1.91 **गरीबी:** गरीबी के संबंध में नवीनतम आंकड़े वर्ष 2011-12 हेतु उपलब्ध हैं। इन अनुमानों को तेन्दुलकर समिति की क्रियाविधि का अनुसरण करते हुए घरेलू उपभोग

व्यय संबंधी सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 13.7 प्रतिशत तथा समग्र रूप से देश में 21.9 प्रतिशत अनुमानित है।

1.92 **मानव विकासः अंतर्राष्ट्रीय तुलनाः** 2014 की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 187 देशों के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के संबंध में उनका महत्व और स्थान प्रस्तुत करती है। 2013 के लिए भारत का एचडीआई महत्व 0.586 है जो उसे 187 देशों और क्षेत्रों में से 135वां स्थान दिलाता है जो ब्रिक्स देशों में सबसे निम्नतम हैं जबकि रूस 57वें, ब्राजील 79वें, चीन 91वें और दक्षिण अफ्रीका 118वें स्थान पर है। किन्तु भारत का स्थान बांग्लादेश और पाकिस्तान से थोड़ा-सा ऊपर है। महिला विकास सूचकांक (जीडीआई) के संबंध में भी भारत का स्थान नीचे है। भारत का जीडीआई महत्व 0.828 है तथा 148 राष्ट्रों में भारत का स्थान 132वां है। इसकी तुलना में बांग्लादेश और चीन का स्थान ऊपर है।

1.93 **समावेशी विकास को प्रोत्साहित करनाः** अगस्त, 2014 में, प्रधानमंत्री जन-धन योजना और रूपे कार्ड की शुरूआत हुई, जो भुगतान का एक साधन है, वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। इसके अलावा, सरकार ने, चल रहे अनेक कार्यक्रमों की क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर पुनर्संरचना की है जिससे कि उन्हे आवश्यकता आधारित बनाया जा सके। विभिन्न सामाजिक अवसंरचनाओं और मानव विकास कार्यक्रमों के समन्वित रूप से कार्य करने हेतु सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) को शुरू किया गया है जिससे मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। एक अन्य शुरू की गई योजना वनबन्धू कल्याण योजना है जिसे अनुसूची V के 10 राज्यों में से प्रत्येक के एक खण्ड में कार्यान्वित किया जाएगा समावेश विकास को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वित की गई बहु योजनाओं के कारण पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ करने की जरूरत है। सामाजिक सेवाओं से संबंधित आरबीआई के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वैश्विक संकट 2008-09 और यूरो क्षेत्र संकट 2011-12 के दौरान भी आम सरकार (केन्द्र+राज्य) द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए संपूर्ण व्यय में निरन्तर रूप से वृद्धि हुई थी।

1.94 भारत की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसके अलग-अलग राज्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन में एक-दूसरे से आगे-पीछे हैं। गत दो दशकों के दौरान, दक्षिण भारत में जननक्षमता में होने वाली भारी कमी के कारण दक्षिण भारत में, उत्तर भारत की तुलना में जनसांख्यिकीय परिवर्तन अधिक है। उदाहरणस्वरूप, 2020 में जनसंख्या की लक्षित औसत आयु 29 वर्ष कुछ राज्यों में अधिक हो गई है; इन राज्यों में केरल (33 वर्ष), गोवा (32.3), तमिलनाडु (31.3), हिमाचल प्रदेश (30.4), पंजाबी (29.9), आंध्र प्रदेश (29.3) और पश्चिम बंगाल (29.1) शामिल है।

जलवायु परिवर्तन एवं स्थायी विकास

1.95 जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास पर विश्व द्वारा किए जाने वाले नए करारों के आलोक में वर्ष 2015 के एक अभिप्रेरणा वर्ष होने की संभावना है। यह अगले पंद्रह वर्षों के लिए वैश्विक समुदाय हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास और पर्यावरणीय नीति संबंधी कार्यसूची के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसी) के अंतर्गत हुई बातचीत के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 2015 तक एक वैश्विक करार सामने आ सकता है जो अभिसमय लागू होने वाले सभी देशों को 2020 से जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्रवाई करने हेतु होगा। इसके साथ-साथ, सरकारों के बीच में 2015 में समाप्त हो रहे मिलेनियम विकास लक्ष्यों के स्थान पर सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित एक नए उत्तर 2015 विकास कार्यसूची पर कार्य करने हेतु आपसी सहमति बन गई है।

1.96 नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों (आईपीसीसी एआर 5) द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 2^0C से नीचे बने रहने हेतु, विश्व वर्ष 2100 तक औद्योगिक क्रांति के तहत सभी प्रकार के स्रोतों से केवल 2,900 गीगा-टन कार्बन-डाई-ऑक्साईड की मात्रा का उत्सर्जन करे। 2011 तक, विश्व पहले ही 1,900 गीगाटन कार्बन-डाई-ऑक्साईड उत्सर्जित कर चुका है और अब तक इस बजट के लगभग दो-तिहाई हिस्से का उपभोग कर चुका है। इसका अर्थ यह है कि 2,900 गीगाटन के कुल बजट में वर्तमान से वर्ष 2100 तक केवल 1,000 गीगाटन CO_2 का ही उत्सर्जन किया जा सकता है। इसलिए उत्सर्जन को घटाने की प्रतिबद्धता को तैयार करने हेतु प्रमुख मुद्दा यही है कि हम इस शेष कार्बन बजट का आबंटन सभी देशों के बीच इस तरीके से करें कि जो सभी के लिए उचित और उनके हासिल करने योग्य हो।

1.97 अलग-अलग देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में समग्र रूप से बड़ी भिन्नता है। 2013 में, संपूर्ण कार्बन डाइआक्साइड

उत्सर्जन के संबंध में चीन, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं और भारत इनसे काफी पीछे है। फिर भी, 2013 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का स्थान 196 देशों में से नीचे के 100 देशों में आता है।

1.98 एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने स्वयं स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन के संबंध में अपने लिए नीतियां तैयार की हैं। भारत, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक है। भारत, नई वैज्ञानिक सूचनाओं और विकसित प्रौद्योगिकी के आलोक में एनएपीसीसी के तहत अपने सभी राष्ट्रीय अभियानों पर एक बार फिर काम कर रहा है ताकि अनेक क्षेत्रों जैसे विद्युत उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस को कम करना, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन तथा पवन ऊर्जा, स्वास्थ्य, अवशिष्ट तत्वों से ऊर्जा का उत्पादन इत्यादि पर नए अभियान शुरू करने की संभावनाओं को तलाशने में अतिरिक्त मध्यस्थताओं को शामिल किया जा सके। सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में वित्त जुटाने हेतु भारत की संस्थागत क्षमता को बनाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनुकूलन कार्यों की सहायतास्वरूप 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ 'राष्ट्रीय अनुकूलन निधि' स्थापित की गई है ताकि कृषि, जल और वन आदि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हाल में की गई कुछ प्रमुख पहलों में सोलर मिशन को 20,000 मेगावॉट से पांच गुना करके 100,000 मेगावॉट तक बढ़ाना शामिल है जिसके लिए 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की जरूरत है तथा स्थायी विकास हेतु एकीकृत नीतियों के साथ ''100 स्मार्ट शहरों'' का विकास तथा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एवं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता योजना के विकास हेतु तैयारी भी शामिल है।

1.99 भारत के सामने कई गुना चुनौतियां हैं। भारत शहरीकरण और बढ़ने की दहलीज पर खड़ा है। जनसंख्या बढ़ने से प्रत्येक प्रमुख सेवा की मांग में भी पांच से सात गुणा वृद्धि हो जाएगी। गरीबी उन्मूलन, खाद्य एंव ऊर्जा सुरक्षा, शहरी अवशिष्ट प्रबंधन, जल अभाव इत्यादि की वर्तमान चुनौतियों के साथ मिलकर ये प्रवृत्तियां हमारे सीमित संसाधनों पर अधिक दबाव डालेंगी जिससे हमारी ऊर्जा की आवश्यकता और बढ़ेगी तथा यदि इन्हें पृथक नहीं किया गया तो यह समानान्तर रूप से उत्सर्जन में वृद्धि होने का कारण बनेंगी। इसके साथ-साथ, इन चुनौतियों में कई बड़े अवसर छुपे हैं। अनेक देशों के विपरीत, भारत के पास बड़ी संख्या में युवा नागरिक हैं और इसलिए यह जनसांख्यिकीय लाभांश के फल को भोग सकेगा। 2030 के भारत के आधे से भी अधिक निर्माण अभीशेष होने के कारण हमारे पास जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा प्रणाली और कार्बन लॉक-इन पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के अवसर हैं जिससे अनेक औद्योगिकृत देश आज जूझ रहे हैं। चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए एक सुविचारित नीति रूपरेखा जिसमें विकासपरक आवश्यकताओं और पर्यावरणपरक विचारों दोनों पर ध्यान दिया गया हो, मददगार साबित हो सकती है।

1.100 संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह हम पश्च-2015 में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक करार की ओर अपने कार्यों को इकट्ठा कर सामने रखते हैं तो यह समग्र रूप से महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनिश्चित करें कि नया करार व्यापक, सन्तुलित, साम्यिक और व्यावहारिक हो। यह भारत जैसे विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो। इसमें भारत जैसे विकासशील देशों को कार्बन तथा विकास हेतु साम्यिक स्थान उपलब्ध हो ताकि विकासशील देश स्थायी विकास और गरीबी-उन्मूलन के अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इसे हासिल करने की कुंजी यूएनएफसीसी के सिद्धान्तों और प्रावधानों की अनुपालना है। वैश्विक जलवायु कार्रवाई महत्वपूर्ण रूप से कार्यान्वयन के साधनों विशेषकर वित्त और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है जिसके लिए करार में पर्याप्त रूप से उपाय होने चाहिए। भारत के प्रधान मंत्री के रूप में, श्री नरेन्द्र मोदी ने, सितम्बर, 2014 में, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा था कि ''चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए। वैश्विक समुदाय, सामुहिक कार्रवाई-समान किन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों के सुंदर सन्तुलन पर सहमत है। यह हमारे अनवरत कार्य का आधार होना चाहिए।